नई दिल्ली
गुरुवार
10 सितंबर 2026
वर्षः 13, अंकः 07
पृष्ठः 08, मूल्य 2 रु0

E-mail
story@sadbhawna.today
sadbhavnatoday@gmail.com
web: www.sadbhawna.today

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र
सद्भावना टुडे
आवाज़ अधिकार की

बिहार के हित में फरक्का जल संधि पर...पेज-05

DELHIN/2014/58158

आम आदमी पार्टी 27 सितंबर से विधानसभा स्तरीय...पेज-08

सबसे करीबी दोस्त और पड़ोसी होने के नाते भारत हमेशा श्रीलंका की मदद करता रहेगाः राजनाथ

भारत ने श्रीलंका में बनाए तीन बेली ब्रिज, रक्षा मंत्री ने किया वर्चुअल उद्घाटन

नई दिल्ली,एजेंसी। तीन दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच कई तरह की साझेदारी के सभी मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने इस बात पर फिर से जोर दिया कि दोनों देश करीबी पड़ोसी और समुद्री पार्टनर के तौर पर भारत और श्रीलंका की भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। साथ ही इस इलाके की सुरक्षा, शांति और खुशहाली पक्की करने के लिए मिलकर काम करेंगे। रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के नागरिकों के बीच मजबूत ऐतिहासिक और सिविलाइजेशनल रिश्तों और लोगों के बीच मेलजोल पर आधारित गहरी दोस्ती है। रक्षा मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए राष्ट्रपति दिसानायके ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी बातचीत को याद करके दोहराया कि श्रीलंका कभी भी अपने इलाके का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी काम के लिए नहीं होने देगा। राष्ट्रपति दिसानायके ने साइक्लोन दितवाह के दौरान 'ऑपरेशन सागर बंधु' के तहत भारत की तरफ से दी गई राहत मदद के लिए शुक्रिया अदा किया।

रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि श्रीलंका का सबसे करीबी दोस्त और पड़ोसी होने के नाते भारत इसे कोई एहसान नहीं, बल्कि सबसे पहले मदद करने वाले के तौर पर मदद देना अपनी जिम्मेदारी समझता है और आगे भी ऐसा करता रहेगा। दोनों नेताओं ने भारतीय सशस्त्र बलों के बनाए तीन बेली ब्रिज का वर्चुअली उद्घाटन किया। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई एयरफोर्स के लिए एल-70 गन्स के अपग्रेडेशन और दोनों देशों के नेशनल कैडेट कॉर्प्स और नेशनल डिफेंस कॉलेज के बीच सहयोग पर समझौता भी किया। इन एयर डिफेंस गन्स के अपग्रेडेशन से श्रीलंका में जरूरी एसेट्स का एयर डिफेंस आर्किटेक्चर काफी मजबूत होगा। ये एयर डिफेंस गन्स पहले भारत ने श्रीलंका एयर फोर्स को दी थीं।

एक नजर

डीआरआई ने देशभर में 740 किलो मादक पदार्थ जब्त किए, 13 गिरफ्तार

नई दिल्ली,एजेंसी। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत पिछले 15 दिनों में देशभर में आठ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 740 किलोग्राम गांजा, हाई-ग्रेड हाइड्रोपोनिक कैनबिस और चरस जब्त की है। इन मामलों में एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि जब्त मादक पदार्थों में 709.6 किलोग्राम गांजा, 24.5 किलोग्राम हाई-ग्रेड हाइड्रोपोनिक कैनबिस तथा पांच किलोग्राम चरस शामिल है। डीआरआई अधिकारियों ने 8 सितंबर को रायपुर के निकट ओल्ड धमतरी रोड पर विशाखापट्टनम से आ रहे दो ट्रकों को रोककर तलाशी ली। इस दौरान ट्रकों के लोडिंग एरिया में रखी 10 बोरियों में छिपाए गए 61 पैकेट बरामद हुए, जिनमें 375.95 किलोग्राम गांजा मिला। दोनों ट्रकों को जब्त कर चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले 26 अगस्त को रायपुर के निकट एक ट्रक से करीब 124 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पांच और छह सितंबर को एक अन्य कार्रवाई में डीआरआई ने पटना के निकट औरंगाबाद-पटना राजमार्ग पर एक ट्रक का पीछा कर उसे रोका। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों पर हमला भी किया गया, जिसमें एक अधिकारी घायल हो गया, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। वाहन की तलाशी में चालक के केबिन के पीछे बने गुप्त कक्ष से 140.5 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। एक और कार्रवाई में एक-दो सितंबर को पंजाब के लुधियाना के पास एक कार से लगभग 69 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। यह मादक पदार्थ वाहन के फर्श में बनाए गए विशेष गुप्त खांचों में छिपाकर रखा गया था। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया।

सुखविंदर सुक्खू की डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात, लैवेंडर खेती एवं एस्ट्रो-टूरिज्म पर हुई चर्चा

नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक में हिमाचल प्रदेश में मौसम पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत बनाने, लैवेंडर खेती के विस्तार, ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान, स्पीति में हाई-एल्टीट्यूड स्काई ऑब्जर्वेटरी तथा राज्य कैडर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के लिए पांच डॉप्लर वेदर रडार उपलब्ध कराने के निर्णय की सराहना की और इसके लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने राज्य की मौसम निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली को और मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इस मौके पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पहाड़ी और प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील हिमाचल प्रदेश में प्रभावी अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करना बेहद जरूरी है। इसके लिए मौसम अवलोकन नेटवर्क के विस्तार पर भी चर्चा की गई। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कुफरी, जोत और मुरारी देवी में तीन डॉप्लर वेदर रडार हैं, जबकि दो अन्य रडार स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा लाहौल-स्पीति और किन्नौर में भी नए रडार लगाने की योजना पर काम चल रहा है। राज्य में 28 ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन, 64 ऑटोमैटिक रेन गेज और 84 दैनिक वर्षा निगरानी केंद्र पहले से संचालित हैं।

भारत 6जी नेतृत्व और सुरक्षा के लिए 'कॉल टू एक्शन' पहल में हुआ शामिल

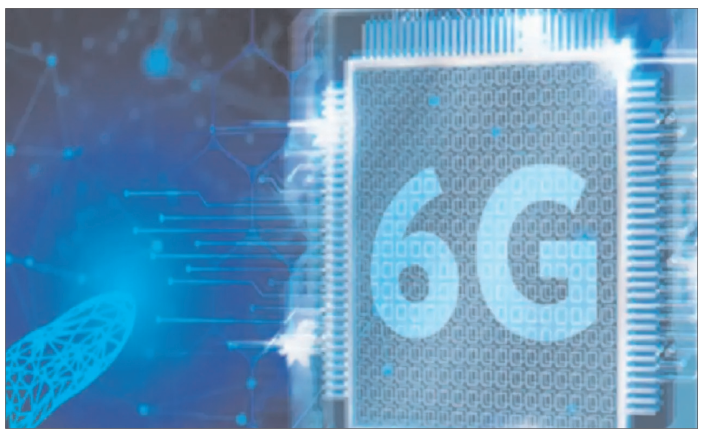

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत ने 6जी नेतृत्व और सुरक्षा के लिए वैश्विक 'कॉल टू एक्शन' पहल का समर्थन किया है। इसके साथ ही भारत उन 20 से अधिक देशों के समूह में शामिल हो गया है, जिन्होंने खुले, परस्पर-संचालित, सुरक्षित, लचीले और नवाचार आधारित अगली पीढ़ी के दूरसंचार नेटवर्क विकसित करने की साझा प्रतिबद्धता जताई है।

संचार मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि इस पहल के तहत भारत की भागीदारी को आगे बढ़ाने और संबंधित गतिविधियों के समन्वय की जिम्मेदारी दूरसंचार विभाग (डीओटी) निभाएगा। विभाग उद्योग, शिक्षाविदों, विभिन्न सरकारी एजेंसियों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर इस दिशा में काम करेगा। मंत्रालय के अनुसार, यह पहल केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के उस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगी, जिसमें भारत को 6जी तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत ने वैश्विक 6जी मानकों और पेटेंट में 10 प्रतिशत योगदान देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस पहल की घोषणा अमेरिका की जी-20 अध्यक्षता में 1 एवं 2 सितंबर को नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित जी-20 इनोवेशन मंत्रिस्तरीय बैठक के अवसर पर की गई। इस दौरान केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री जितिन प्रसाद और अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक के बीच औपचारिक मुलाकात भी हुई। 'कॉल टू एक्शन' के तहत सहभागी देश 6जी नेटवर्क के लिए सुरक्षा, लचीलापन, संसाधन दक्षता और नवाचार आधारित प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा 6जी अनुसंधान एवं विकास, वैश्विक मानकीकरण, सुरक्षित आपूर्ति शृंखला, साइबर सुरक्षा जोखिमों के आकलन और 5जी-6जी तकनीकों के वैश्विक विस्तार में सहयोग को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि भारत की यह भागीदारी 'भारत 6जी विजन', 'भारत 6जी एलायंस' और स्वदेशी 4जी व 5जी तकनीकी ढांचे जैसी पहलों पर आधारित है। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत-2047 के लक्ष्य के अनुरूप यह कदम दूरसंचार क्षेत्र में भारत की वैश्विक भूमिका को और मजबूत करेगा।

शादी से किसी महिला की व्यक्तिगत आजादी खत्म नहीं हो सकतीः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली,एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध के दायरे में लाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस मामले को महिलाओं के अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आपराधिक कानून से जुड़े बड़े संवैधानिक सवाल के रूप में देखा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि संविधान के अलग-अलग हिस्सों में देखकर नहीं समझा जा सकता है। जब अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की बात होती है, तो उसका असर अनुच्छेद 20 के तहत मिलने वाले कानूनी संरक्षण पर भी पड़ता है। मामले पर अगली सुनवाई अब तीन हफ्ते बाद होगी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि शादी से किसी महिला की व्यक्तिगत आजादी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन शादी के अंदर दुष्कर्म के लिए मुकदमा चलाने की इजाजत देने से पहले कोर्ट को भारतीय न्याय संहिता के तहत मौजूदा कानूनी अपवाद पर भी ध्यान देना होगा। कोर्ट ने कहा कि वह दो सवालों पर विचार करेगा। पहला कि क्या वैवाहिक दुष्कर्म से जुड़ी छूट के बावजूद मुकदमा चलाया जा सकता है और दूसरा कि क्या यह छूट खुद संवैधानिक रूप से वैध है। बुधवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने इससे जुड़े मामलों में अपना जवाब दाखिल किया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से नोडल वकील इन सभी दस्तावेजों और दलीलों को एकत्र कर एक सेट तैयार करेंगे और आपस में आदान-प्रदान करेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11 मई, 2022 को वैवाहिक दुष्कर्म के मामले पर विभाजित फैसला दिया था।

जिलों को आर्थिक विकास और सुधार का इंजन बना रहा कौशल विकासः जयंत चौधरी

नई दिल्ली। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने महिलाओं के लिए टिकाऊ आजीविका के अवसर तैयार करने के विषय पर 'स्किल मंथन' का पहला सत्र आयोजित किया। वर्चुअल संवाद में उत्तर प्रदेश के मेरठ और बिजनौर तथा आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले की पहल प्रस्तुत की गईं। इन पहलों में कौशल विकास, उद्यमिता, वित्त, तकनीक और बाजार तक पहुंच को एक साथ जोड़कर महिलाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर तैयार किए जा रहे हैं।

केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि जिला प्रशासन विकास, सुधार और बदलाव के वास्तविक इंजन हैं। जिला आधारित योजना के जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कौशल विकास की पहल स्थानीय जरूरतों के अनुसार तैयार हों और उद्योग, विशेषकर एमएसएमई की आवश्यकताओं से जुड़ी हों।

बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मप्र, छत्तीसगढ़ से जुड़ी तीन मल्टीट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को मंजूरी

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्र सरकार ने बुधवार को 10,783 करोड़ रुपये की लागत वाली रेलवे की तीन मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की। इससे पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क में करीब 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

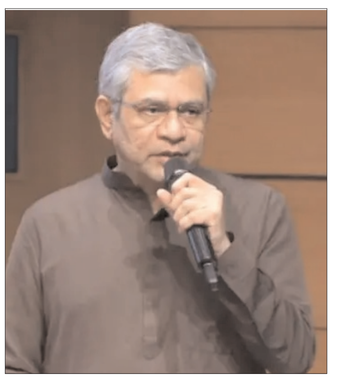

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। वैष्णव ने बताया कि मंजूर परियोजनाओं में खड़गपुर-झारसुगुड़ा (बागदेही) चौथी लाइन, कटनी-पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर (उसलापुर)-पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल हैं। परियोजनाओं को 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इससे 14 जिलों के करीब 4,790 गांवों और 56 लाख लोगों को बेहतर रेल संपर्क मिलने की उम्मीद है। वैष्णव ने कहा कि झारसुगुड़ा से आगे छत्तीसगढ़ के हिस्से में रेल मार्गों पर गंभीर भीड़भाड़ है। पिछले 50-60 वर्षों में इस क्षेत्र में रेल नेटवर्क का पर्याप्त विकास नहीं हुआ। पिछले 12 वर्षों में छत्तीसगढ़ में कई नई रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। आदिवासी बहुल यह क्षेत्र आर्थिक और देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर से पेंड्रा और आगे कटनी तक के मार्ग को चार लाइन का किया जा रहा है। कुछ हिस्सों में पहले से तीन लाइनें हैं, जबकि कुछ में दो लाइनें हैं। यह मार्ग अनूपपुर जैसे महत्वपूर्ण जंक्शन से होकर गुजरता है, जहां से झारखंड के अलावा बिहार और उत्तर प्रदेश की ओर रेल यातायात संचालित होता है। इस मार्ग की क्षमता बढ़ने से यात्री और माल परिवहन दोनों को लाभ मिलेगा तथा भीड़भाड़ कम होगी। सरकार के अनुसार, परियोजनाओं को प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तैयार किया गया है। इनसे मल्टी-मॉडल संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ेगी तथा लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही सुगम होगी। परियोजनाओं से तारातारिणी मंदिर, श्री क्षेत्र जगन्नाथ मंदिर, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, अमरकंटक मंदिर, अचानकमार टाइगर रिजर्व और रतनपुर महामाया मंदिर समेत कई प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। ये मार्ग कोयला, सीमेंट, लौह एवं इस्पात जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। क्षमता विस्तार से सालाना करीब 2.7 करोड़ टन अतिरिक्त माल ढुलाई होने का अनुमान है। इससे करीब 12 करोड़ लीटर तेल आयात और 62 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होने की उम्मीद है, जो करीब 2.48 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।

वित्त मंत्री का इस्तीफा लेकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए भगवंत मान सरकारः राहुल गांधी

नई दिल्ली,एजेंसी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पंजाब में किसान गुलजार सिंह की आत्महत्या के मामले को लेकर राज्य की भगवंत मान सरकार से वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का तत्काल इस्ताफा लेने और मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

राहुल गांधी ने बुधवार को एक्स पोस्ट में आरोप लगाया कि दलित समुदाय से आने वाले गुलजार सिंह ने अपने बेटे के नशे का शिकार होने के बाद वित्त मंत्री से सरकार की ओर से ड्रग्स के कारोबार को रोकने में कथित नाकामी को लेकर सवाल किया था। इसके बाद गुलजार सिंह पर माफी मांगने के लिए दबाव बनाया गया और उन्हें प्रताड़ित तथा अपमानित किया गया। उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम के बाद गुलज़ार सिंह ने जहर खा लिया। गुलजार सिंह को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाया गया और इलाज नहीं मिलने के कारण आखिरकार उनकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि पंजाब में ऐसा यह पहला मामला नहीं है। पिछले सप्ताह उन्होंने मोहनजीत सिंह से भी बात की थी, जिन्हें मुख्यमंत्री मान के खिलाफ प्रदर्शन करने के कारण प्रताड़ित किया गया। राहुल ने कहा कि सरकार का काम जनता के सवालों का जवाब देना है, सवाल पूछने वालों को कुचलना नहीं। उन्होंने गुलज़ार के परिवार को जल्द न्याय दिलाने की मांग करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करनी चाहिए तथा जांच की प्राथमिकी में वित्त मंत्री का नाम दर्ज किया जाना चाहिए।

दिल्ली के लिए अलग इंजीनियरिंग कैडर को केंद्र की मंजूरी

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के 3,214 स्वीकृत इंजीनियरिंग पदों को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) कैडर से अलग कर स्वतंत्र दिल्ली पीडब्ल्यूडी इंजीनियरिंग कैडर के रूप में संचालित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र की मंजूरी का स्वागत करते हुए कहा कि अलग इंजीनियरिंग कैडर बनने से दिल्ली में निर्माण कार्यों को गति मिलेगी और अधिकारियों की जवाबदेही तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह दिल्ली को विकसित, सुरक्षित और विश्वस्तरीय राजधानी बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।

मुख्यमंत्री के अनुसार दिल्ली पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरिंग विंग में 36 श्रेणियों के कुल 3,214 स्वीकृत पद अब तक सीपीडब्ल्यूडी कैडर के अंतर्गत आते थे। इन पदों पर नियुक्तियां केंद्र सरकार की व्यवस्था के माध्यम से होती थीं। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था के कारण राजधानी की स्थानीय विकास आवश्यकताओं के अनुरूप इंजीनियरिंग अधिकारियों की तैनाती और प्रशासनिक निर्णय लेने में कई बार कठिनाई होती थी। रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी के पास लंबे समय से अपना स्वतंत्र इंजीनियरिंग कैडर नहीं था। करीब 30 वर्षों से यह विषय लंबित था। उनकी सरकार ने दिल्ली की विकास जरूरतों को देखते हुए पीडब्ल्यूडी के लिए अलग इंजीनियरिंग कैडर बनाने का निर्णय लिया था, जिसे अब केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है।

उन्होंने कहा कि राजधानी में लगातार सड़कों, पुलों, सरकारी भवनों, कार्यालयों और अन्य सार्वजनिक ढांचों का निर्माण एवं रखरखाव किया जाता है। ऐसे में दिल्ली की अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सक्षम और स्वतंत्र इंजीनियरिंग तंत्र जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग कैडर के बाद दिल्ली सरकार इंजीनियरिंग व्यवस्था को अपनी जरूरतों के अनुसार अधिक प्रभावी ढंग से संचालित कर सकेगी। इससे इंजीनियरों की उपलब्धता, रिक्त पदों को भरने, परियोजनाओं की निगरानी और निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को आने वाले समय में नया सचिवालय, सभी 11 जिलों में मिनी सचिवालय, मंडियों, खेल मैदानों और अन्य प्रशासनिक एवं सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े भवनों का निर्माण करना है। इसके अलावा सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े कार्य भी किए जाने हैं। इन परियोजनाओं के लिए मजबूत इंजीनियरिंग तंत्र की जरूरत होगी। केंद्र की मंजूरी के बाद दिल्ली पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरिंग विंग के 3,214 स्वीकृत पद सीपीडब्ल्यूडी कैडर से अलग होकर स्वतंत्र दिल्ली पीडब्ल्यूडी इंजीनियरिंग कैडर के तहत संचालित होंगे। सरकार का मानना है कि इससे दिल्ली इंजीनियरिंग सेवाओं के क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर हो सकेगी।

छात्रों ने सौंपी पर्यावरण मंत्री को दिल्ली-एनसीआर में स्वच्छ वायु को बढ़ावा देने संबंधी रिपोर्ट

सैफुल्लाह सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार

नई दिल्ली। साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय तथा उसके दिल्ली केंद्र के विभिन्न विषयों से जुड़े छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपने शैक्षणिक अधिकारियों के साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से बुधवार को मुलाकात की। इस अवसर पर दिल्ली के पर्यावरण एवं वन विभाग के सचिव विजय कुमार बिधूड़ी भी उपस्थित रहे। छात्रों ने प्रोमोटिंग क्लीन एयर इन दिल्ली एनसीआर (दिल्ली-एनसीआर में स्वच्छ वायु को बढ़ावा देना) शीर्षक से एक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें क्षेत्र में वायु प्रदूषण की चुनौती का विश्लेषण करते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जा रही सर्वोत्तम व्यवस्थाओं के आधार पर कई उपाय सुझाए गए हैं।

अध्ययन में रेखांकित किया गया कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण मूल रूप से पूरे एयरशेड (वायुमंडलीय क्षेत्र) से जुड़ी चुनौती है, क्योंकि प्रदूषण के स्रोत राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं तक सीमित नहीं हैं। इसमें समन्वित कार्रवाई, बेहतर निगरानी, स्रोत-विशिष्ट उपायों और पूर्वानुमान आधारित क्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया गया, जिसमें पूरे एनसीआर में समन्वय शामिल हो। छात्रों का स्वागत करते हुए और उनके अध्ययन की सराहना करते हुए मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान और सतत भविष्य के निर्माण में युवाओं की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, 'नई पीढ़ी के पास नए विचार, नई ऊर्जा और पारंपरिक सोच को नया रूप देने का साहस है। दिल्ली की पर्यावरणीय चुनौतियां जटिल और व्यापक हैं, लेकिन नवाचार, प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से इनका समाधान किया जा सकता है। हम युवाओं और शैक्षणिक संस्थानों के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनके विचार हमें ऐसे समाधान तलाशने में मदद कर सकते हैं, जो व्यावहारिक होने के साथ-साथ परिवर्तनकारी भी हों। मंत्री ने दिल्ली के सामने मौजूद विशाल अपशिष्ट प्रबंधन चुनौती को भी रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 13,000 मीट्रिक टन कचरा उत्पन्न होता है, जो न्यूजीलैंड में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले कचरे से भी अधिक है। इसके अतिरिक्त दिल्ली में लगभग 30,000 से 35,000 मीट्रिक टन पुराने कचरे का भी प्रसंस्करण किया जा रहा है। इस प्रकार प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले कचरे और वर्षों से जमा पुराने कचरे—दोनों के प्रबंधन का दायित्व सरकार के सामने है, जो इस चुनौती के विशाल स्तर को दर्शाता है। मंत्री ने कहा, 'दिल्ली को केवल आज उत्पन्न होने वाले कचरे का ही प्रबंधन नहीं करना है, बल्कि वर्षों से जमा पुराने कचरे की समस्या का भी समाधान करना है। इसका पैमाना बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण भी उतना ही महत्वाकांक्षी है। हम वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन, अधिक से अधिक संसाधन पुनर्प्राप्ति और सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ताकि कचरे को केवल समस्या के रूप में नहीं, बल्कि एक संसाधन के रूप में देखा जा सके। साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा प्रस्तुत अध्ययन में वैश्विक अनुभवों के आधार पर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। इनमें परिवहन के लिए उत्सर्जन-आधारित नियमन, ईंट भट्ठों के प्रदर्शन मानकों में सुधार, पराली को आर्थिक मूल्य प्रदान करना, मौजूदा अनौपचारिक नेटवर्क के माध्यम से रीसाइक्लिंग को औपचारिक रूप देना, खाना पकाने के लिए प्रदूषण रहित साधनों को बढ़ावा देना तथा पूर्वानुमान आधारित एयरशेड प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना शामिल हैं। अध्ययन में इस बात पर जोर दिया गया कि दिल्ली के वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान अलग-अलग और बिखरे हुए उपायों के माध्यम से नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक एकीकृत, सार्वजनिक रूप से सुलभ और पूर्वानुमान आधारित एयरशेड प्रणाली की आवश्यकता है, जिसमें सैटेलाइट से प्राप्त आंकड़े, जमीनी स्तर की निगरानी, मौसम संबंधी पूर्वानुमान और प्रदूषण के स्रोतों का वैज्ञानिक विश्लेषण शामिल हो तथा पूरे एनसीआर में समन्वित

दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआईए से पूछा- क्या कड़ी शर्तों के साथ इंजीनियर रशीद को दी जा सकती है नियमित जमानत

शाहनवाज सैफ, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने टेरर फंडिंग मामले के आरोपित और सांसद इंजीनियर रशीद की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए नेशनल इंवेस्टिगेटिव एजेंसी (एनआईए) से पूछा है कि क्या केवल दिल्ली में रहने जैसी कड़ी शर्तों के आधार पर जमानत दी जा सकती है। जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने एनआईए की ओर से पेश वकील से इस सवाल पर निर्देश लेकर आने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी।

सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से पेश वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि इंजीनियर रशीद के खिलाफ पर्याप्त तथ्य हैं कि उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। लूथरा ने कहा कि एक बार जब रशीद को जमानत मिली थी तो उन्होंने एक गवाह को प्रभावित करने की कोशिश की थी। इस बात का सबूत कॉल डाटा रिकॉर्ड से मिल सकता है। उन्होंने कहा कि रशीद के खिलाफ गंभीर आरोप हैं कि वे एक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में एक आतंकी के संपर्क में थे। लूथरा ने कहा कि इस मामले में दो गवाहों के बयान महत्वपूर्ण है। इन दो गवाहों में से एक गवाह संरक्षित गवाह है। तब उच्च न्यायालय ने कहा कि दोनों गवाहों के बयान सुनवाई की अगली तिथि के पहले दर्ज किए जाएं। इसके पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने रशीद को संसद सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी। कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इंजीनियर रशीद को अपने पिता की मौत के बाद 40वें दिन के रस्म में हिस्सा लेने के लिए 25 जून से 30 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी। इंजीनियर रशीद के पिता की 18 मई को एम्स अस्पताल में मौत हो गई थी।

इंजीनियर रशीद ने लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करीब एक लाख मतों से हराकर जीत हासिल की थी। राशिद इंजीनियर को 2016 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था।पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 मार्च 2022 को हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन, यासिन मलिक, शब्बीर शाह और मसरत आलम, राशिद इंजीनियर, जहूर अहमद वताली, बिट्टा कराटे, आफताब अहमद शाह, अवतार अहम शाह, नईम खान, बशीर अहमद बट्ट ऊर्फ पीर सैफुल्ला समेत दूसरे आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। एनआईए के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सहयोग से लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिद्दीन, जेकेएलएफ, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों ने जम्मू-कश्मीर में आम नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमले और हिंसा को अंजाम दिया।

विनेश फोगाट की याचिका पर हाई कोर्ट ने डब्ल्यूएफआई से अपना पक्ष रखने को कहा

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने महिला पहलवान विनेश फोगाट की 2026 सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए चयन ट्रायल में हिस्सा लेने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए भारतीय कुश्ती संघ (डब्ल्यूएफआई) को अपना पक्ष रखने को कहा है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने इस मामले पर 17 सितंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया।

विनेश फोगाट ने ये नई अर्जी अपनी याचिका में दी है। लंबित याचिका में फोगाट ने अपने गर्भावस्था और मातृत्व अवकाश के बाद खेल में वापसी करने वाली महिला खिलाड़ियों के लिए एक स्पष्ट नीति बनाने की मांग की है। नई अर्जी में फोगाट ने भारतीय कुश्ती संघ के 7 सितंबर के उस सर्कुलर पर रोक लगाने की मांग की है, जिसके तहत उसे चयन प्रक्रिया से बाहर रखा गया। नई अर्जी में कहा गया है कि भारतीय कुश्ती महासंघ को दिशा-निर्देश दिया जाए कि फोगाट को फिलहाल पात्र खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया जाए और 14 सितंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने वाले महिला चयन ट्रायल में हिस्सा लेने दिया जाए। ये चयन ट्रायल भारत की उस टीम के चयन के लिए है जिसे 24 अक्टूबर से एक नवंबर तक कजाकिस्तान के अस्ताना में होने वाली 2026 सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हिस्सा लेना है। भारतीय कुश्ती महासंघ के सर्कुलर के मुताबिक 14 सितंबर को दिल्ली में छह ओलंपिक भार वर्गों में महिला पहलवानों के चयन ट्रायल होंगे।

रेल राज्यमंत्री ने दिल्ली मंडल के नियंत्रण कार्यालय का किया निरीक्षण

नई दिल्ली,एजेंसी। रेल राज्यमंत्री वी. सोमन्ना ने बुधवार को दिल्ली मंडल के नियंत्रण कार्यालय का दौरा कर रेलवे परिचालन, सुरक्षा, ट्रेनों के समयपालन और यात्रियों की शिकायतों से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत कर रेलवे परिचालन में सुधार के लिए तकनीक के अधिक इस्तेमाल और कर्मचारियों की कार्यस्थितियों को बेहतर बनाने पर भी चर्चा की।

सोमन्ना ने दिल्ली मंडल के मंडल रेल प्रबंधक पुष्पेश आर. त्रिपाठी और उनकी टीम के साथ विस्तृत चर्चा की। उन्होंने नियंत्रण कार्यालय में सेक्शन कंट्रोलरों के कामकाज के अलावा इंजीनियरिंग, कोचिंग, माल, वाणिज्यिक, सिग्नल एवं दूरसंचार, ट्रैक्शन और सुरक्षा नियंत्रण से जुड़ी गतिविधियों का जायजा लिया। उन्होंने अत्याधुनिक सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन (एससीएडीए) केंद्र और दिल्ली मंडल के 'वार रूम' का भी निरीक्षण किया। रेल मंत्रालय के अनुसार, मंडल का नियंत्रण कार्यालय चौबीसों घंटे ट्रेनों के परिचालन, रखरखाव की योजना, निगरानी और सुरक्षा संबंधी गतिविधियों का केंद्र होता है। दिल्ली मंडल रेलवे के सबसे जटिल प्रशासनिक मंडलों में शामिल है।

मंत्री ने रेलवे परिचालन, सुरक्षा निगरानी और रखरखाव में तकनीक के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित प्रणालियों से मानवीय त्रुटियों को कम करने और सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिली है। भविष्य में 'मेक इन इंडिया' सहित अन्य नीतिगत पहलों के माध्यम से इन प्रयासों को और मजबूत किया जाएगा। सोमन्ना ने रेलवे कर्मचारियों के अनुशासन, समर्पण और कठिन परिश्रम की सराहना करते हुए कहा कि रेलकर्मी चौबीसों घंटे काम करते हैं और उनका समर्पण सेना के जवानों की प्रतिबद्धता के समान है। उन्होंने परिचालन दक्षता, सुरक्षा निगरानी और तकनीक आधारित नियंत्रण व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया।

BRICS सम्मेलन की तैयारियों को लेकर MCD-PWD का संयुक्त निरीक्षण

नई दिल्ली,सद्भावना टुडे। राजधानी दिल्ली में प्रस्तावित BRICS सम्मेलन 2026 की तैयारियों को लेकर दिल्ली नगर निगम और लोक निर्माण विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बुधवार को निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने PWD के प्रधान सचिव संदीप कुमार के साथ राजधानी के प्रमुख क्षेत्रों का संयुक्त निरीक्षण कर जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। संयुक्त निरीक्षण की शुरुआत भारत मंडपम और उसके आसपास के क्षेत्रों से हुई। इस दौरान निगम आयुक्त ने सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता एवं अन्य नागरिक सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ सफाई व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए। निगम अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि BRICS सम्मेलन से जुड़े सभी प्रमुख मार्गों, आयोजन स्थलों, बाजारों, सड़कों, फुटपाथों, ग्रीन बेल्ट और संवेदनशील स्थानों पर विशेष एवं गहन सफाई सुनिश्चित की जाए। अधिकारियों से कहा गया कि सम्मेलन के दौरान किसी भी स्तर पर सफाई व्यवस्था में कमी नहीं रहनी चाहिए। संयुक्त टीम ने सराय काले खां, लोधी रोड और निजामुद्दीन सहित दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के प्रमुख क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया। इन क्षेत्रों में सम्मेलन में आने वाले प्रतिनिधियों एवं अन्य आगंतुकों के आवागमन को देखते हुए व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। निगम आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि BRICS सम्मेलन के अंतिम एवं महत्वपूर्ण चरण के दौरान प्रमुख स्थानों पर पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मचारी, मशीनरी और पर्यवेक्षण व्यवस्था उपलब्ध रहे। उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर लगातार निगरानी रखने और आवश्यकतानुसार तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद टीम ने साकेत और शेख सराय क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान स्वच्छता के साथ-साथ सड़कों, फुटपाथों, हरित क्षेत्रों और सार्वजनिक सुविधाओं की स्थिति का जायजा लिया गया। निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि चिन्हित क्षेत्रों में स्वच्छता, सड़क एवं फुटपाथ, हरित क्षेत्र, सार्वजनिक सुविधाएं, प्रवर्तन, पशु नियंत्रण, वेक्टर नियंत्रण, सौंदर्यीकरण, प्रकाश व्यवस्था और ब्रांडिंग में स्पष्ट एवं प्रभावी सुधार किया जाए। निरीक्षण के दौरान संबंधित जोनों के उपायुक्तों के अलावा MCD और PWD के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों को सम्मेलन की तैयारियों से जुड़े कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने तथा विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने के निर्देश दिए गए। दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार का कहना है कि BRICS सम्मेलन में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों के साथ-साथ दिल्लीवासियों और राजधानी में आने वाले आगंतुकों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और स्वागतपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।

खतरनाक भवनों पर MCD का शिकंजा

एक दिन में 34 भवन ध्वस्त, 17 संपत्तियां सील

शबाना बेगम, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। सत्य निकेतन भवन हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम ने राजधानी में खतरनाक और अवैध भवनों के खिलाफ अपना अभियान और तेज कर दिया है। बुधवार को एमसीडी के सभी 12 जोनों में व्यापक कार्रवाई करते हुए कुल 34 भवनों पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई। इसके अलावा 17 संपत्तियां सील, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए तथा 4 ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए। एमसीडी के अनुसार, यह कार्रवाई दिल्ली के मास्टर प्लान, भवन उपनियमों के उल्लंघन, अनधिकृत निर्माण और संरचनात्मक रूप से असुरक्षित भवनों के खिलाफ की जा रही है। इससे एक दिन पहले भी निगम ने 17 संपत्तियों को ध्वस्त और 5 को सील किया था।

अभियान के दौरान कूचा चेलन, जामा मस्जिद स्थित एक संपत्ति में ग्राउंड फ्लोर की छत के दो पैनल और पार्टिशन दीवार को ध्वस्त किया गया। पुलिस की सहायता से हुई इस कार्रवाई में अनधिकृत निर्माण हटाया गया। बाजार सीताराम में भी अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं विकास नगर और सेक्टर-17, द्वारका में खतरनाक घोषित भवनों को कार्रवाई के दायरे में लिया गया। राणा प्रताप बाग में कार्रवाई के दौरान तीसरी मंजिल की आरसीसी छत के चार पैनल और पहली मंजिल के आरसीसी स्लैब का एक पैनल तोड़ा गया। सरिया काटने के साथ दूसरी मंजिल की ईंट की दीवारें भी हटाई गईं। सरदार नगर, मॉडल टाउन में तीन आरसीसी स्लैब पैनल ध्वस्त किए गए और सरिया काटा गया।

खतरनाक भवनों के साथ-साथ दिल्लीभर में संचालित पेइंग गेस्ट (PG) भवनों का व्यापक सर्वेक्षण भी तेज कर दिया गया है। एमसीडी का उद्देश्य ऐसे भवनों का डेटाबेस तैयार कर सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील इमारतों की पहचान करना है। अब तक करीब 1,243 PG भवनों की पहचान की जा चुकी है, जहां लगभग 24,000 लोग रह रहे हैं। निगम विशेष रूप से 5 से अधिक मंजिल वाले RCC फ्रेम्ड भवनों और 4 से अधिक मंजिल वाले लोड-बेयरिंग भवनों की जांच कर रहा है। सर्वेक्षण के बाद भवनों को उनकी स्थिति के आधार पर सुरक्षित, मामूली मरम्मत योग्य, व्यापक मरम्मत योग्य तथा संवेदनशील/खतरनाक श्रेणी में रखा जाएगा। एमसीडी ने सर्वेक्षण का कार्य 10 सितंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। निगम ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन, अनधिकृत निर्माण या संरचनात्मक कमजोरी मिलने पर संबंधित भवनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राजधानी में लगातार सामने आ रहे जर्जर और असुरक्षित भवनों को लेकर एमसीडी ने अब प्रवर्तन अभियान को व्यापक रूप देने के संकेत दिए हैं। आने वाले दिनों में चिन्हित संपत्तियों पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई और तेज होने की संभावना है।

दिल्ली एयरपोर्ट पर बाढ़ का फर्जी वीडियो फैलाने के आरोप में 63 सोशल मीडिया हैंडल पर एफआईआर

नई दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (आईजीआई) पर जलभराव का भ्रामक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप में 63 सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (डीआईएएल) ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस में शिकायत दी है। आरोप है कि इन हैंडल से एयरपोर्ट पर जलभराव और परिचालन प्रभावित होने का गलत दावा करते हुए वीडियो एवं पोस्ट प्रसारित किए गए।

डीआईएएल के अनुसार, एक सोशल मीडिया पोस्ट में दुबई एयरपोर्ट पर जलभराव का पुराना वीडियो दिल्ली एयरपोर्ट का बताकर वायरल किया गया। कंपनी का कहना है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री एयरपोर्ट की वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाती थी। इस तरह की भ्रामक पोस्ट से यात्रियों में अनावश्यक भ्रम और चिंता पैदा हुई तथा महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुविधा की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। चार सितंबर को दिल्ली में हुई तेज बारिश के दौरान एयरपोर्ट क्षेत्र में भी भारी वर्षा हुई थी। दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे के बीच एयरपोर्ट क्षेत्र में करीब 72.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

इसके कारण टर्मिनल-3 के आगमन क्षेत्र में कुछ समय के लिए पानी जमा हो गया था। डीआईएएल ने कहा कि एयरपोर्ट टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए करीब 20 मिनट के भीतर जमा पानी को साफ कर दिया। इसके बाद एयरपोर्ट का परिचालन निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत सामान्य और सुरक्षित रूप से जारी रहा। कंपनी ने स्पष्ट किया कि जलभराव की इस अस्थायी स्थिति से एयरपोर्ट के परिचालन पर कोई असर नहीं पड़ा। डीआईएएल के प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट से प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री यात्रा करते हैं और उनकी सुरक्षा तथा परिचालन की विश्वसनीयता कंपनी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तेज बारिश के कारण टर्मिनल-3 के आगमन क्षेत्र में अस्थायी जलभराव हुआ था, लेकिन इसे 20 मिनट में सामान्य कर दिया गया।

गीताकॉलोनी फ्लाईओवर के पास ऑटो रोककर डेढ़ करोड़ लूटे, बाइक सवार तीन बदमाश फरार

नई दिल्ली। गीताकॉलोनी फ्लाईओवर के पास बाइक सवार तीन बदमाशों ने हथियार के बल पर ऑटो रुकवाकर डेढ़ करोड़ रुपये से भरा बैग लूट लिया। वारदात सोमवार शाम करीब 7:30 बजे आउटर रिंग रोड पर हुई। वारदात के बाद आरोपित आइटीओ की तरफ फरार हो गए। शिकायत मिलने के बाद दरियागंज थाना पुलिस ने मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की कई टीमें सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के आधार पर बदमाशों की पहचान में जुटी हैं। पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता अपने एक सहकर्मी के साथ ऑटो में सवार होकर चांदनी चौक से सफदरजंग एन्क्लेव जा रहा था। दोनों के पास एक बैग में करीब 1.5 करोड़ रुपये की नकदी थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक, यह रकम उसके नियोक्ता की थी। वह चांदनी चौक में भुगतान वसूली और सामान पहुंचाने का काम करता है। जैसे ही ऑटो गीताकॉलोनी फ्लाईओवर के पास पहुंचा, मोटरसाइकिल सवार तीन बदमाशों ने ऑटो को रोक लिया। आरोप है कि बदमाशों में से एक ने हथियार निकालकर शिकायतकर्ता और उसके साथी को धमकाया। इसके बाद बदमाश नकदी से भरा बैग छीनकर मोटरसाइकिल से आइटीओ की तरफ भाग गए। अचानक हुई वारदात से पीड़ित और उसका साथी सकते में आ गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। पुलिस को आशंका है कि बदमाशों ने पहले से रेकी की होगी और उन्हें नकदी ले जाने की जानकारी रही होगी। ऐसे में शिकायतकर्ता के आने-जाने के रास्ते और उसके काम से जुड़े लोगों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। इस मामले में दरियागंज थाने में एफआईआर संख्या 329/2026 दर्ज की गई है।

सत्य निकेतन हादसा : मृतकों के परिजनों को 2-2 करोड़ मुआवजा दे सरकार : देवेंद्र यादव

सद्भावना टुडे, संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सत्य निकेतन में पीजी छात्रावास की पांच मंजिला इमारत ढहने की दर्दनाक घटना में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को 2-2 करोड़ रुपये तथा हादसे में घायल छात्रों को 50-50 लाख रुपये का तत्काल मुआवजा देने की मांग की है। देवेंद्र यादव ने कहा कि हादसे में मृत पांच छात्रों की पहचान अभिषेक, युवराज सोनी, पवन, अर्पित जाज और अक्षत सिंह यादव के रूप में हुई है। इसके अलावा मृतकों में एक मजदूर और क्षेत्र का एक वृद्ध निवासी भी शामिल है। उन्होंने मांग की कि इन मृतकों के परिवारों को भी 2-2 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कोई भी धनराशि उन माता-पिता के दर्द और अपूरणीय क्षति की भरपाई नहीं कर सकती, जिन्होंने अपने बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा दिलाने के लिए काफी त्याग और आर्थिक खर्च किया था। देश के विभिन्न हिस्सों से छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में अपने उज्ज्वल भविष्य का सपना लेकर आते हैं, लेकिन एक इमारत के ढहने से उनके सपने और परिवारों की उम्मीदें पल भर में तबाह हो गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों के लालच, भ्रष्टाचार और अधिकारियों की कथित लापरवाही के कारण यह भयावह हादसा हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार को इस घटना की जिम्मेदारी तय करने के साथ-साथ पीड़ित परिवारों को तत्काल पर्याप्त आर्थिक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए।

देवेंद्र यादव ने कहा कि हादसे में घायल छात्रों को पूरी तरह स्वस्थ होने में कई महीने लग सकते हैं। उन्हें इलाज, पुनर्वास और दोबारा पढ़ाई शुरू करने के दौरान आर्थिक मदद की जरूरत होगी। इसलिए प्रत्येक घायल छात्र को 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए, ताकि वे उपचार के बाद अपनी शिक्षा जारी रख सकें और अपने भविष्य को फिर से संवार सकें। उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले अधिकांश छात्रों के माता-पिता सामान्य परिवारों से आते हैं। वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए अपनी क्षमता से अधिक त्याग करते हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों से दिल्ली आने वाले छात्रों के लिए सुरक्षित और किफायती छात्रावास की व्यवस्था बेहद जरूरी है। यादव ने कहा कि विश्वविद्यालय में छात्रावास की सीटें पर्याप्त नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में छात्र निजी पीजी में रहने को मजबूर हैं। बाहर से आने वाले छात्रों के लिए सुरक्षित पीजी आवास सुनिश्चित करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने समय रहते गंभीर प्रयास नहीं किए। अब सरकार द्वारा आने वाले महीनों में पीजी आवास के लिए विशेष नीति बनाने की बात कही जा रही है। देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली में अकेले रहकर शिक्षा प्राप्त करना छात्रों के लिए पहले ही चुनौतीपूर्ण है और सुरक्षित आवास की समस्या इसे और गंभीर बना देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली सरकार ने छात्रावास सुविधाओं को उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बड़े-बड़े वादे तो करती है, लेकिन उन्हें जमीन पर लागू करने में विफल रहती है। उन्होंने मांग की कि सत्य निकेतन हादसे के पीड़ित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता दी जाए और दिल्ली में छात्रों के लिए सुरक्षित, सस्ती एवं पर्याप्त छात्रावास और पीजी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ठोस नीति बनाई जाए।

एक नजर

दिल्ली जल बोर्ड एसटीपी घोटाले के चार और आरोपितों को मिली जमानत

नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड एसटीपी घोटाले के चार आरोपितों को जमानत दे दी है। स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने चारों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने उदित प्रकाश राय, नागेंद्र यादव, पंकज वर्मा और अंकित श्रीवास्तव को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इसके पहले कोर्ट दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत दे चुका है। सत्येन्द्र जैन और दूसरे आरोपितों को 18 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। सत्येन्द्र जैन की ओर से पेश वकील मनिंदर सिंह ने जैन की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया था। उन्होंने कहा था कि जैन को गिरफ्तार करते समय गिरफ्तारी की वजह नहीं बताई गई, जो उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।

एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) ने सत्येंद्र जैन के अलावा दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व कॉन्ट्रैक्टुअल कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव, मेसर्स एएन एंटरप्राइजेज के मालिक नागेंद्र यादव, मेसर्स यूरोटेक एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजा कुमार कुर्रा और मेसर्स सृजनहार के मालिक पंकज वर्मा को एसीबी की उस एफआईआर के मामले में गिरफ्तार किया था, जो 11 मई, 2024 को भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओं 7, 7, 9, 13 और भारतीय दंड संहिता की धाराओं 42, 409, 418, 120-बी के तहत दर्ज की गई थी। एसीबी का आरोप है कि टेंडर की शर्तें एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई थीं।

दिन दहाड़े युवक की हत्या

बागपत। बागपत जिले के बड़ौत नगर की अति व्यस्त खत्री गढ़ी क्षेत्र में बुधवार को दिनदहाड़े युवक की हथौड़े से वार कर हत्या कर दी गई। आरोपित पति-पत्नी मोके से फरार है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान 35 वर्षीय दीपेंद्र के रूप में हुई है। बताया गया कि दीपेंद्र खत्री गढ़ी वह एक इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सेंटर पर नौकरी करता था। बुधवार को वह क्षेत्र में मौजूद था। इसी दौरान उसका चाय की दुकान चलाने वाले दंपती से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर दंपती ने दीपेंद्र पर हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आरोपी दंपती ने दीपेंद्र के साथ मारपीट की जिसमे उसके सिर में चोट लग गई। गंभीर चोट लगने से दीपेंद्र मौके पर ही गिर पड़ा। आसपास के लोगों के पहुंचने से पहले ही आरोपित दंपती मौके से फरार हो गया। दिनदहाड़े हुई इस वारदात के बाद खत्री गढ़ी में लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि वारदात से जुड़े साक्ष्य जुटाए जा सकें। कोतवाली प्रभारी दीक्षित त्यागी का कहना है कि वारदात के पीछे क्या कारण रहा और दंपती ने किस विवाद के चलते दीपेंद्र पर हमला किया, इसकी जांच की जा रही है। परिजनों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस फरार आरोपित दंपती की तलाश में दबिश दे रही है। सीओ बड़ौत अंशु जैन का कहना है कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ जारी है।

नोएडा में एमबीए के छात्र सहित तीन ने की आत्महत्या

नोएडा। नोएडा में थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र के सेक्टर 150 स्थित जेपी अमन सोसायटी में रहने वाले एमबीए के छात्र ने 22 वीं मंजिल से कूदकर आज आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना नॉलेज पार्क के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि मौर्य पटेल 26 वर्ष पुत्र जगदीश कुमार पटेल मूल निवासी नौचंडी जनपद मेरठ मौजूदा समय में सेक्टर 150 स्थित जेपी अमन सोसायटी में अपने एक दोस्त के साथ रहते थे। वह एमिटी यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे, तथा ऑनलाइन कुछ काम भी करते थे। पढ़ाई के दौरान वह परीक्षा पास नहीं कर पा रहे थे। इस बात को लेकर वह तनाव में थे। उन्होंने बताया कि आज मौर्य पटेल ने अपनी सोसाइटी की 22वीं मंजिल से नीचे को छलांग लगा दिया। इस घटना में उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

थाना सूरजपुर के प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने बताया कि आकाश (26 वर्ष) पुत्र योगेंद्र मूल निवासी जनपद हजारीबाग झारखंड थाना सूरजपुर क्षेत्र में रहते थे। उन्होंने मानसिक तनाव के चलते अपने घर पर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक ने कोई सुसाइड नोट नहीं लिखा है। पुलिस आत्महत्या के कारण का पता लगा रही है। थाना ईकोटेक -3 के प्रभारी निरीक्षक मुनेद्र कुमार सिंह ने बताया कि मूल रूप से जमुई बिहार की रहने वाली आंचल पुत्री सत्येंद्र थाना ईकोटेक 3 क्षेत्र के कुलेसरा कालोनी में रहती थी। वह कुछ दिनों से बीमार थी। इस वजह से वह मानसिक तनाव में थी। उन्होंने मानसिक तनाव के चलते आज सुबह को अपने घर पर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया है। उन्होंने बताया कि मृतका के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना फेस -वन के प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि थाना क्षेत्र में एक 34 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव आज मिला है।

बिल्डिंग गिरती है, अधिकारी गिरते हैं—जवाबदेही कब तय होगी ?

सद्भावना टुडे, संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली में जब कोई इमारत भरभराकर गिरती है तो मलबे के नीचे सिर्फ ईंट-पत्थर नहीं दबते, बल्कि कई परिवारों के सपने, उम्मीदें और भविष्य भी दफन हो जाते हैं। हादसा होता है, मातम मनता है, नेता बयान देते हैं, जांच के आदेश होते हैं और फिर कुछ अधिकारियों पर गाज गिराकर मामला धीरे-धीरे ठंडा पड़ जाता है।

लेकिन असली सवाल वहीं खड़ा रहता है—आखिर जवाबदेही सिर्फ एमसीडी अधिकारियों की ही क्यों ?

क्या किसी वार्ड में अवैध निर्माण रातों-रात खड़ा हो जाता है ? क्या वर्षों तक चलने वाली निर्माण गतिविधियां किसी को दिखाई नहीं देतीं ? क्या स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की स्थिति की जानकारी नहीं होती ? और अगर होती है, तो फिर अवैध निर्माण तथा खतरनाक इमारतों पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं होती ?

अधिकारी ही दोषी हैं तो बाकी जिम्मेदार कौन ?

हर हादसे के बाद अधिकारियों पर कार्रवाई करना आसान है। निलंबन कर दीजिए, तबादला कर दीजिए, जांच बैठा दीजिए और जनता को बता दीजिए कि सरकार ने सख्त कदम उठा लिया। लेकिन क्या इससे अगली इमारत गिरने से रुक जाएगी ?

सिर्फ अधिकारियों को सजा देने से व्यवस्था की सड़ांध दूर नहीं होगी। यदि किसी इलाके में वर्षों से अवैध निर्माण चलता है, नियमों की धज्जियां उड़ती हैं और शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होती, तो जिम्मेदारी तय करने का दायरा भी व्यापक होना चाहिए।

जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही से क्यों बचती है व्यवस्था ?

निगम पार्षद जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। अपने वार्ड की समस्याओं, अवैध गतिविधियों, अतिक्रमण और स्थानीय परिस्थितियों से वे पूरी तरह अनजान रहें—यह सवाल अपने आप में गंभीर है। इसीलिए यह मांग उठना स्वाभाविक है कि दिल्ली के सभी 250 निगम पार्षदों की पिछले चार वर्षों की संपत्ति का स्वतंत्र और पारदर्शी परीक्षण कराया जाए। किसी को दोषी ठहराना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सवाल केवल इतना है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले जनप्रतिनिधियों की संपत्ति में हुई वृद्धि उनके घोषित आय-स्रोतों से मेल खाती है या नहीं—इसकी जांच क्यों नहीं हो सकती ?

अगर सब कुछ पाक-साफ है तो जांच से डर कैसा ?

'विकसित भारत' के साथ 'विकसित जवाबदेही' भी जरूरी

केन्द्र सरकार विकसित भारत का सपना देख रही है। दिल्ली देश की राजधानी है और यहां ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें किसी गरीब, मजदूर या बाहर से रोजी-रोटी की तलाश में आए परिवार को अवैध निर्माण की कीमत अपनी जान देकर न चुकानी पड़े। बिल्डिंग गिरने के बाद मलबा हटाना प्रशासन की मजबूरी है, लेकिन बिल्डिंग गिरने से पहले भ्रष्ट व्यवस्था का मलबा हटाना सरकार की जिम्मेदारी है। अब जरूरत बयानबाजी की नहीं, बल्कि जवाबदेही की पूरी श्रृंखला तय करने की है।

अधिकारी दोषी हैं तो कार्रवाई हो।

जनप्रतिनिधि की भूमिका संदिग्ध है तो जांच हो।

निर्माणकर्ता दोषी है तो कानून अपना काम करे।

और यदि भ्रष्टाचार की मिलीभगत सामने आती है तो किसी भी स्तर के व्यक्ति को बख्शा न जाए।

हर हादसे के बाद एक अधिकारी को बलि का बकरा बनाकर फाइल बंद करने की परंपरा अब बंद होनी चाहिए।

क्योंकि सवाल सिर्फ एक इमारत का नहीं है।

सवाल दिल्ली के उन हजारों परिवारों की जिंदगी का है, जो इस शहर में सुरक्षित छत की उम्मीद लेकर रहते हैं।

सद्भावना टुडे का सीधा सवाल

इमारत गिरने पर अधिकारी नपते हैं,

लेकिन अवैध निर्माण की पूरी व्यवस्था कब नपेगी ?

मलबे में दबकर मरने वालों को इंसाफ कब मिलेगा ?

और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही कब तय होगी ?

आआपा ने राघव चड्ढा के फॉर्म-6 पर उठाए सवाल, फॉर्म सार्वजनिक करने की मांग

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आआपा) ने राघव चड्ढा के दिल्ली की मतदाता सूची में नाम जुड़ने को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि राघव चड्ढा के कथित तौर पर भरे गए फॉर्म-6 को सार्वजनिक किया जाए और यह बताया जाए कि उनका नाम मतदाता सूची में किस तारीख और किस प्रक्रिया के तहत जोड़ा गया।

आआपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चुनाव आयोग की प्रक्रिया में मनमानी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से यह बताया गया है कि राघव चड्ढा ने फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाया, लेकिन आयोग ने यह स्पष्ट नहीं किया कि फॉर्म-6 कब भरा गया और उसे किस प्रक्रिया के तहत मंजूरी दी गई। ढांडा ने कहा कि चुनाव आयोग के अनुसार 30 जून से 17 अगस्त तक गणना प्रपत्र भरे जा सकते थे। फॉर्म-6 के माध्यम से नाम जोड़ने के मामलों पर 31 अगस्त से 30 सितंबर तक आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। इसके बाद निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) संबंधित आवेदन पर निर्णय करता है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या स्थानांतरित करने के लिए फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 निर्धारित प्रक्रियाएं हैं। आआपा नेता ने कहा कि राघव चड्ढा के मामले में फॉर्म-8 के जरिए स्थानांतरण संभव नहीं है, क्योंकि पंजाब की मतदाता सूची से दिल्ली में उनका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पंजाब के एसआईआर में चड्ढा को 'शिफ्टेड' के रूप में चिह्नित किया गया है। उन्होंने फॉर्म-7 का चड्ढा के मामले से संबंध होने से इनकार किया और कहा कि अब केवल फॉर्म-6 ही संभावित विकल्प बचता है। ढांडा ने सवाल किया कि यदि राघव चड्ढा ने दिल्ली में फॉर्म-6 भरा है तो चुनाव आयोग बताए कि वह फॉर्म कब और कहां भरा गया। उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा का फॉर्म-6 सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि पार्टी के पास एक से सात सितंबर के बीच राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में भरे गए फॉर्म-6 की सूची है और उसमें राघव चड्ढा का नाम नहीं है। आआपा नेता ने मतदाता सूची में राघव चड्ढा के कथित सीरियल नंबर को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि चड्ढा का सीरियल नंबर किस आधार पर आया, इसकी जानकारी आयोग को देनी चाहिए।

ओखला में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एक की मौत, चार घायल

अशोक कुमार, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। दिल्ली के ओखला फेज-1 में बुधवार सुबह व्यावसायिक ऑक्सीजन सिलेंडर में जोरदार धमाका होने से एक कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए। हादसा डी-23 स्थित एसएम ट्रेडर्स के गोदाम के बाहर उस समय हुआ, जब गाजियाबाद से लाए गए ऑक्सीजन सिलेंडरों को वाहन से उतारा जा रहा था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि एक सिलेंडर वाहन से फिसलकर सड़क पर गिरा और जमीन से टकराते ही उसमें विस्फोट हो गया। धमाके की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस के मुताबिक, बुधवार सुबह करीब 10:43 बजे ओखला इंडस्ट्रियल एरिया थाने में सिलेंडर फटने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही थाना पुलिस, जांच अधिकारी, एसएचओ, एसीपी, पीसीआर और इमरजेंसी रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर टाटा 407 वाहन (डीएल-1एलएजे-3232) खड़ा मिला। पुलिस के अनुसार, वाहन एसएम ट्रेडर्स के नाम से पंजीकृत है और इसमें गाजियाबाद से व्यावसायिक ऑक्सीजन सिलेंडर लाए गए थे।

प्रारंभिक जांच के अनुसार, उमेश, मोहित और पंकज समेत अन्य कर्मचारी वाहन से सिलेंडर उतार रहे थे। इसी दौरान एक सिलेंडर फिसलकर सड़क पर जा गिरा। जमीन पर गिरते ही उसमें जोरदार धमाका हो गया। शुरुआती जांच में केवल एक सिलेंडर के फटने की जानकारी सामने आई है। धमाके में करीब 35 वर्षीय मोहित सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वह मूल रूप से जयपुर का रहने वाला था और पिछले करीब तीन वर्षों से एसएम ट्रेडर्स में हेल्पर के तौर पर काम कर रहा था। हादसे में उमेश, अरविंद, मनोज और पंकज घायल हुए हैं। चारों को तत्काल एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। पुलिस उनकी पहचान और मेडिकल स्थिति की जानकारी जुटा रही है। पुलिस जांच में सामने आया है कि डी-23 स्थित परिसर में एसएम ट्रेडर्स का गोदाम है। फर्म करीब एक-दो साल से किराये के परिसर में काम कर रही है और जीएसटी पंजीकरण के तहत संचालित बताई जा रही है। यहां करीब तीन-चार कर्मचारी काम करते हैं। फर्म औद्योगिक ऑक्सीजन सिलेंडरों की स्थानीय ट्रेडिंग और सप्लाई का काम करती है। पुलिस के मुताबिक, परिसर में ऑक्सीजन भरने का कोई प्लांट नहीं मिला है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, गाजियाबाद के सप्लायर राम अवतार से भरे हुए सिलेंडर ओखला लाए जाते थे। इसके बाद इन्हें स्थानीय औद्योगिक इकाइयों और कारोबारियों को सप्लाई किया जाता था। रोजाना करीब 70 से 80 सिलेंडरों की आवाजाही होने की बात सामने आई है। हालांकि, पुलिस स्टॉक रजिस्टर, खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड, बिल और अन्य दस्तावेजों की जांच के बाद ही इस आंकड़े की पुष्टि करेगी। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि सिलेंडरों के भंडारण, रखरखाव और परिवहन के लिए जरूरी अनुमति और लाइसेंस फर्म के पास थे या नहीं। इसके अलावा सिलेंडरों के स्वामित्व, सप्लायर की भूमिका और आपूर्ति के स्रोत की भी जांच की जा रही है। घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया गया है। तकनीकी और फोरेंसिक टीम मौके से साक्ष्य जुटा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फोरेंसिक और तकनीकी जांच पूरी होने के बाद ही सिलेंडर में धमाका होने की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी।

कपिल मिश्रा ने एस्केप ड्रेन वन, बिहारीपुर, बंड और गोकलपुर ड्रेन का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के एस्केप ड्रेन वन, बिहारीपुर ड्रेन, बंड ड्रेन और गोकलपुर ड्रेन निरीक्षण कर संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सोनिया विहार पुश्ता से जुड़े विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। कपिल मिश्रा ने जलभराव से निपटने के लिए ड्रेन की सफाई व पम्पिंग व्यवस्था को और मजबूत करने और इन कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए और कहा कि पानी के ओवर फ्लो होकर रिहायशी क्षेत्रों में घुसने के स्थायी समाधान की ओर बढ़ना है। इस दौरान उन्होंने सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी एवं दिल्ली जल बोर्ड अधिकारियों को समन्वय बनाकर स्वच्छता एवं विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। कपिल मिश्रा ने पीडब्ल्यूडी को गीतांजलि स्कूल वजीराबाद रोड से गोकलपुर मेट्रो स्टेशन तक स्टॉर्म वाटर ड्रेन का प्रस्ताव तैयार कर जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने एस्केप ड्रेन वन में बाउंड्री वाल निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और इसे जल्द पूरा करने के साथ ही लोगों को जागरूक करने की अपील भी की ताकि लोग ड्रेन में कचरा न फेंकें।

कपिल मिश्रा ने एमसीडी को गोकलपुर ड्रेन की डिसिल्टिंग जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही दिल्ली जल बोर्ड को भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले वेस्ट वाटर को ड्रेन में न डालने और इसकी वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने सोनिया विहार पुश्ता के सर्विस रोड निर्माण एवं फुटपाथ निर्माण को लेकर भी निर्देश दिए। उन्होंने खजूरी खास फ्लाई ओवर के नीचे पीडब्ल्यूडी को सौंदर्यीकरण के भी निर्देश दिये। कपिल मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ड्रेनों की सफाई और पम्पिंग व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ड्रेनों की क्षमता, पम्पिंग व्यवस्था, जल प्रवाह और निकासी बिंदुओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम जनता को जलभराव, गंदगी और खराब जल निकासी के कारण किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जलभराव की समस्या को रोकने के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें और संवेदनशील स्थानों पर आवश्यक तैयारियां पहले से सुनिश्चित की जाएं।

नोएडा में अवैध रूप से पटाखा का भंडारण करने वाला गिरफ्तार

नोएडा। थाना बिसरख पुलिस ने अवैध रूप से पटाखा का भंडारण करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उनके पास से दर्जनों पेटियों में भरे हुए लाखों रुपये कीमत का विस्फोटक बरामद किया है। पुलिस ने विभिन्न जगहों से चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। थाना बिसरख के प्रभारी निरीक्षक रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि उप निरीक्षक विपिन कुमार ने आज सुबह एक सूचना के आधार पर नितिन गर्ग पुत्र मुकेश कुमार गर्ग को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि इसके पास से पुलिस ने पेटियों के अंदर भरे हुए अवैध पटाखे बरामद किया है। बरामद पटाखे की कीमत लाखों रुपये है। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला है कि आरोपित आगामी त्योहारों के मद्देनजर पटाखों का अवैध भंडारण करने के लिए पटाखे लेकर आया था। थाना प्रभारी ने बताया कि एक अन्य मामले में उप निरीक्षक सुशील कुमार ने दीपू कुमार पुत्र संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस ने 24 पाउच देशी शराब बरामद किया है।

अरविंदो कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने दिल्ली विधानसभा का किया शैक्षणिक भ्रमण

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के अरविंदो कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने बुधवार को युवा आउटरीच कार्यक्रम के तहत दिल्ली विधानसभा का शैक्षणिक भ्रमण किया। विद्यार्थियों ने विधानसभा परिसर का अवलोकन किया तथा दिल्ली विधानसभा के इतिहास, इसकी गौरवशाली विरासत, लोकतांत्रिक परंपराओं और विधायी कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की।

इस अवसर पर छात्र-छात्राओं ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से मुलाकात की और उनके साथ लोकतंत्र, संविधान, विधायिका की भूमिका तथा राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक संवाद किया। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक अपने प्रश्न रखे और विधानसभा की कार्यप्रणाली तथा सदन में होने वाली चर्चाओं को लेकर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। विद्यार्थियों से संवाद करते हुए विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी लोकतांत्रिक संस्थाओं को नजदीक से जानने और समझने में विशेष रुचि ले रही है। उन्होंने कहा कि जेन-जी भारत की जागरूक, जिज्ञासु और ऊर्जावान पीढ़ी है तथा लोकतंत्र को मजबूत बनाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र को केवल एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि संवाद, विचार-विमर्श, सहमति, असहमति और संवैधानिक मर्यादाओं पर आधारित एक जीवंत व्यवस्था के रूप में समझना आवश्यक है। दिल्ली विधानसभा का भ्रमण युवाओं को यह समझने का अवसर देता है कि जनप्रतिनिधि किस प्रकार जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से जनहित से जुड़े विषयों को आगे बढ़ाया जाता है। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने दिल्ली विधानसभा के ऐतिहासिक परिसर का निर्देशित भ्रमण किया तथा इसकी समृद्ध स्थापत्य एवं संस्थागत विरासत से परिचित हुए। विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई जिससे वे इस भवन के केंद्रीय विधान सभा से जुड़े ऐतिहासिक संबंधों के साथ-साथ इससे संबंधित महत्वपूर्ण संसदीय विभूतियों और ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जान सके।

सीसीटीवी फुटेज ने खोला घर में चोरी का राज, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। कालिंदी कुंज थाना पुलिस ने जैतपुर एक्सटेंशन की खड्डा कॉलोनी में घर में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान इस्माइल (22) निवासी अलीया फार्म, बसंतपुर गांव, हरियाणा के रूप में हुई है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी किए गए सोने-चांदी के गहने और नकदी बरामद की है। चोरी का सामान खरीदने के आरोप में पुलिस ने जाकिर नगर निवासी अनीश (27) को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, पांच सितंबर को जैतपुर एक्सटेंशन की खड्डा कॉलोनी निवासी रहीश ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घर से बाहर गए थे। इसी दौरान शाम करीब 4:15 बजे उनके घर में चोरी हो गई। चोर खिड़की के ऊपर लगे कांच के पैनल को खोलकर घर में दाखिल हुआ था। घर से तीन सोने की अंगूठियां, एक सोने का नेकलेस सेट, 20 हजार रुपये, दो जोड़ी चांदी की पायल और एक जोड़ी बालियां चोरी हुई थीं। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच टीम ने घटनास्थल और आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज के साथ तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची। पुलिस को आठ सितंबर को इस्माइल के बारे में पुख्ता सूचना मिली। इसके बाद टीम ने अलीया फार्म, बसंतपुर टोल के पास घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की वारदात में शामिल होने की बात स्वीकार की। उसने बताया कि चोरी के गहने उसने जाकिर नगर निवासी अनीश को 38 हजार रुपये में बेच दिए थे। इसके बाद पुलिस ने इस्माइल की निशानदेही पर अनीश को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस्माइल के कब्जे से एक जोड़ी सोने की बालियां, एक सोने की अंगूठी, एक जोड़ी चांदी की पायल और 2,490 रुपये नकद बरामद किए हैं। पुलिस चोरी हुए अन्य सामान की बरामदगी के लिए पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार, इस्माइल पहले भी चार आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। वहीं, सरिता विहार थाना पुलिस ने सड़क हादसे के एक मामले में लंबे समय से फरार चल रहे घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है।

डीयू के हर कॉलेज में हॉस्टल की मांग पर हाई कोर्ट का केंद्र, दिल्ली सरकार और विश्वविद्यालय को नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) के हर कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ये महत्वपूर्ण याचिका है लेकिन याचिकाकर्ता ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को पक्षकार क्यों बनाया है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप यूजीसी को पक्षकार की सूची से हटाएं।

याचिका एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने दायर की है। सात सितंबर को याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई करने की मांग की थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा था कि सत्य निकेतन में पीजी वाली बिल्डिंग के गिरने के मामले पर 7 सितंबर को ही सुनवाई हुई थी। आपकी याचिका पर 9 सितंबर को सुनवाई होगी। बुधवार को जनहित याचिका पर सुनवाई का दिन है। आप याचिका दाखिल कीजिए ये अपने आप बुधवार को लिस्ट हो जाएगी। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। सत्य निकेतन में पीजी वाली बिल्डिंग के गिरने के मामले पर 7 सितंबर को ही सुनवाई हुई थी। सात सितंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम को निर्देश दिया था कि वो दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक बिल्डिंग के अचानक भरभराकर गिरने के मामले की उच्च-स्तरीय जांच करे। उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य सरकार इस मामले की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।

सवालों के जवाब देकर इस पीढ़ी की पीड़ा करें दूर

विश्वनाथ सचदेव

लगभग तेरह साल पुरानी बात है। तब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री-पद के उम्मीदवार थे। अपनी योग्यता-क्षमता को दिखाने के लिए उनके पास गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में किया गया काम था। उसी दौरान उन्होंने राजधानी दिल्ली के एक कॉलेज में एक भाषण दिया था। उस भाषण में वह सब था, जो एक उम्मीदवार मतदाता को रिझाने के लिए कह सकता है। सपना दिखाया गया था, वादे किए गए थे। उस भाषण का एक जुमला बहुत चर्चित हुआ था तब—आधे भरे और आधे खाली गिलास वाला मुहावरा। आशावाद और निराशावाद का अंतर समझाने के लिए अक्सर यह उदाहरण दिया जाता है और कहा जाता है कि वह आशावादी है, जो गिलास को आधा भरा हुआ बताता है और जो कहता है कि गिलास आधा खाली है, वह निराशावादी है। तब नरेंद्र मोदी ने इस मुहावरे में एक बात और जोड़ी थी, जिसने इस घिसी-पिटी बात को 'ताज़गी' दे दी थी। नरेंद्र मोदी ने कहा था, 'मुझे वह गिलास पूरा भरा हुआ दिखाई दे रहा है—आधा पानी से, और आधा हवा से। तेरह साल बाद नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के रूप में दिल्ली के उसी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में छात्रों को, और इसके बहाने देश को, संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। अवसर कॉलेज के शताब्दी समारोह का था और जो विद्यार्थी उन्हें सुनने के लिए पहुंचे थे, वे तब शायद किसी स्कूल में पढ़ते होंगे।

जिन्होंने तेरह साल पहले वाला 'पूरे भरे गिलास' वाला भाषण सुना था, उन्हें वह याद भी था और मेरी तरह शायद वे यह उम्मीद भी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री पूरे भरे गिलास वाली अपनी बात दोहराएंगे। और प्रधानमंत्री ने भी अपनी कही उस बात को दोहराना ज़रूरी समझा। सामने बैठे विद्यार्थियों के लिए यह बात नई थी। उन्हें भी प्रधानमंत्री का आशावाद अच्छा लगा। तब भावी प्रधानमंत्री ने सपने दिखाए थे, अब वर्तमान प्रधानमंत्री 'अपना रिपोर्ट कार्ड' लेकर उपस्थित थे। पिछले तेरह साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार की उपलब्धियों को गिनाना शायद स्वाभाविक था। खूब गिनाईं, और तालियां भी बजीं। प्रधानमंत्री यह जानते थे कि कॉलेज में पढ़ने वाली जिस पीढ़ी को वे संबोधित कर रहे हैं, वह 'जेन ज़ी' नए मुहावरों को समझती है। देश के युवकों की एक अपनी भाषा है, अपना मुहावरा है उनका। प्रधानमंत्री ने कोशिश की उनसे उनकी भाषा में बात करने की। यह पीढ़ी सपने देखने के बजाय ठोस उपलब्धियों की जानकारी चाहती है। उपलब्धियां गिनाईं उन्होंने। पर यह 'जेन ज़ी' सवाल उठाने वाली है। उपलब्धियों को स्वीकारा जाना चाहिए, पर ऐसे मौके आत्मान्वेषण के भी होते हैं। यह अवसर एक प्रसिद्ध शिक्षा-संस्थान की शताब्दी का था। विद्यार्थी उस शिक्षा-स्थिति के बारे में भी सुनना चाहते थे, जो आज के भारत की चिंता का विषय होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले लगभग अस्सी साल में देश में अनेक महत्वपूर्ण शिक्षा-संस्थान खुले हैं। एक लंबी-चौड़ी सूची है हमारे पास नए-नए आई.आई.टी. और आई.आई.एम. की। लेकिन यह सवाल भी उठता रहा है कि हमारे शिक्षा-संस्थानों को वैश्विक स्वीकार्यता क्यों नहीं मिल पाई। प्राथमिक कक्षाओं से लेकर शिक्षा के उच्चतम पायदान पर दी जा रही शिक्षा आज सवालों के घेरे में क्यों है? गुणवत्ता और बुनियादी शिक्षा के स्तर पर बनी चुनौतियों को हम कब देखेंगे—स्वीकारेंगे? लगभग 17 साल पहले हमने देश के नागरिकों के लिए शिक्षा के अधिकार को स्वीकारा था। सर्वशिक्षा अभियान जैसी पहल से स्थिति में कुछ सुधार आया है। पर प्राथमिक शिक्षा में जितना और जैसा सुधार अपेक्षित था, वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आए दिन सरकारी स्कूलों के बंद होने और निजी स्कूलों के खुलने के समाचार मिल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की स्थिति को लेकर पिछले कुछ दिनों में देश में ढेरों सवाल उठे हैं। एक-एक कमरे में चार-चार कक्षाएं एक साथ लग रही हैं। स्कूलों में टाट-पट्टी और शौचालय जैसी ज़रूरी सुविधाओं का भी अभाव है। 'असर' जैसी संस्थाएं बार-बार इस स्थिति को उजागर कर रही हैं कि पांचवीं में पढ़ने वाला बच्चा तीसरी कक्षा की किताबें भी ठीक से नहीं पढ़ पा रहा। जहां तक उच्च शिक्षा का सवाल है, उसकी स्थिति भी कुल मिलाकर निराशाजनक ही है। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजों की पढ़ाई भी उस स्तर की नहीं है कि डिग्री प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी रोज़गार की अपेक्षाओं की शर्तों पर खरा उतर सके। उच्च शिक्षा के लिए हमारे विद्यार्थी विदेशों में जाने को प्राथमिकता क्यों देते हैं? प्रधानमंत्री अंतरिक्ष में 'स्पेस सेंटर' बनाने का सपना तो दिखा रहे हैं, पर धरती पर दुर्दशा की हकीकत की गंभीरता को कब समझा जाएगा?

श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अपने चर्चित भाषण में प्रधानमंत्री ने नई पीढ़ी से जुड़ने का प्रयास अवश्य किया है, पर पूरे भाषण पर चुनावी-साया दिखाई दे रहा है। यह अवसर एक प्रसिद्ध कॉलेज की शताब्दी का था और संयोग से उस दिन शिक्षक-दिवस भी था। यही नहीं, कुछ ही अरसा पहले देश ने 'जेन ज़ी' का असंतोष देखा था और इसी बीच ग्रामीण इलाकों के स्कूलों की दुर्दशा का मसला भी उभर कर सामने आया है। ऐसे में यह अपेक्षा तो होनी ही चाहिए थी कि प्रधानमंत्री देश में शिक्षा की स्थिति और समस्या पर कुछ कहेंगे। पर इस संदर्भ में कुछ विशेष नहीं कहा उन्होंने। देश की जनता के समक्ष अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना भी ज़रूरी होता है, पर यह कतई ज़रूरी नहीं है कि हमारे राजनेता चुनावी माहौल से उबर ही न सकें। उबरना चाहिए उन्हें। भाषणों में जुमले और मुहावरे अच्छे लगते हैं, पर हमेशा नहीं। शिक्षा-जगत से जुड़े एक महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री ने हवा से भरे हुए गिलास और 'दिमाग़ी नक्सल' वाली अपनी बातों को दोहराना ज़रूरी समझा, यह उनका विशेषाधिकार है। युवा पीढ़ी से जुड़ने की उनकी अपनी कोशिश में भी कुछ ग़लत नहीं है, बल्कि ज़रूरी है इस पीढ़ी से जुड़ना, उसकी आकांक्षाओं और चिंताओं को समझना। पर 'नाराज़ फूफा' जैसे जुमले ऐसी कोशिशों को हल्का ही बनाते हैं। हमारे समय और समाज की आवश्यकता है कि नई पीढ़ी को समझने की ईमानदार कोशिश हो। राजनीतिक नफे-नुकसान से ऊपर उठकर इस पीढ़ी को समझना होगा। उसकी पीड़ा और उसकी नाराज़गी को भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। वह निराश है तो उसकी निराशा को समझने की कोशिश होनी चाहिए; वह सवाल उठा रही है तो उसके सवालों के जवाब देने की कोशिश होनी चाहिए। बीबीसी ने श्रीराम कॉलेज के कार्यक्रम के बाद कुछ युवाओं से बातचीत की थी। उनमें एक युवक वह भी था, जिसे इसलिए कार्यक्रम में प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि वह काली कमीज़ पहने हुए था! उसने बीबीसी के संवाददाता को बताया कि शायद आयोजकों को लगा था कि काली कमीज़ खतरे की घंटी है। मान लेना चाहिए कि उस युवक का कोई ग़लत इरादा नहीं था। उसका काली कमीज़ पहनकर आना एक संयोग हो सकता है। पर यह तय है कि देश की जेन-ज़ी अथवा जेन-अल्फा के पास कुछ सवाल हैं, जो उसे परेशान करते हैं। हमारे नेतृत्व को उनकी परेशानी को समझना होगा। तभी गिलास सही अर्थों में भरेगा।

आरक्षण का उद्देश्य अवसरों से वंचित वर्गों को आगे बढ़ने का मंच देना है, न कि किसी मेधावी की योग्यता की अधिकतम सीमा तय करना। अनारक्षित श्रेणी कोई अलग सामाजिक वर्ग या जाति नहीं है, बल्कि यह एक खुली प्रतियोगिता है जहाँ मेरिट में आने वाला कोई भी योग्य अभ्यर्थी स्थान पाने का हकदार है। इस विधिक सिद्धांत को न्यायिक व्यवस्था ने समय-समय पर स्पष्ट और सुदृढ़ किया है। रजत यादव बनाम राजस्थान राज्य (उच्च न्यायालय) मामले में शीर्ष अदालत ने यह सिद्धांत दोहराया कि यदि किसी आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी, जिसने कोई विशेष रियायत नहीं ली है, सामान्य वर्ग के कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो उसे चयन के मध्यवर्ती व प्रारंभिक चरणों में भी खुली श्रेणी की मेरिट सूची में स्थान मिलना चाहिए। उसे केवल उसकी श्रेणी के नाम पर खुली प्रतिस्पर्धा से अलग-थलग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाम शाम कृष्णा बी में भी उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि आरक्षण रोस्टर और नियमों का मनमाना क्रियान्वयन मेधा को नकारने का माध्यम नहीं बन सकता; मेरिट में ऊपर रहने वाला आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में समायोजित होने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार रखता है। यह विसंगति पीसीएस जैसी बहु-चरणीय परीक्षाओं के प्रारंभिक स्तर पर सबसे घातक साबित होती है। यद्यपि प्रारंभिक परीक्षा के अंक अंतिम चयन सूची में नहीं जुड़ते, किंतु यह मुख्य परीक्षा तक पहुँचने का निर्णायक प्रवेश-द्वार है।

ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी की दुविधा

अभिषेक शुक्ल

विगत कुछ वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। जब भी किसी बड़ी भर्ती का विज्ञापन आता है, तो एक बुनियादी सवाल लगातार चर्चा के केंद्र में रहता है— 'भाई, ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरें या अनारक्षित से?' यह सवाल जितना सहज प्रतीत होता है, वास्तव में उतना ही गंभीर है। यह केवल आवेदन-पत्र के किसी एक विकल्प को चुनने का मामला नहीं है, बल्कि एक युवा के भविष्य, उसकी वर्षों की तपस्या और संवैधानिक व्यवस्था पर उसके भरोसे से जुड़ा प्रश्न है। अभ्यर्थी यह जानना चाहता है कि यदि वह अनारक्षित श्रेणी के कटऑफ से अधिक अंक अर्जित करता है, तो क्या व्यवस्था उसकी योग्यता का सम्मान करते हुए उसे खुली प्रतियोगिता का हक देगी? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) प्रारंभिक परीक्षा के आधिकारिक आंकड़े इस दुविधा को किसी काल्पनिक आशंका के बजाय एक कड़वी जमीनी सच्चाई साबित करते हैं। वर्ष 2020 से 2023 तक के आंकड़ों पर दृष्टि डालें तो यह विसंगति निरंतर गहरी होती दिखाई देती है। वर्ष 2020 में जहां अनारक्षित वर्ग का कटऑफ 110 अंक था, वहीं ईडब्ल्यूएस का कटऑफ 112 अंक रहा। वर्ष 2021 में अनारक्षित के 115 अंकों के मुकाबले ईडब्ल्यूएस का कटऑफ 117 अंक, और 2022 में अनारक्षित के 111 अंकों की तुलना में ईडब्ल्यूएस का कटऑफ 114 अंक दर्ज किया गया। वर्ष 2023 में तो यह अंतर चार अंकों तक पहुंच गया, जहां अनारक्षित का कटऑफ 125 अंक था, जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए यह 129 अंक तक चला गया।

इन आंकड़ों का सीधा और त्रासद अर्थ यह है कि वर्ष 2023 में 126, 127 या 128 अंक हासिल करने वाला ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी प्रारंभिक चरण में ही प्रतियोगिता से बाहर हो गया, जबकि उससे कम यानी 125 अंक पाने वाला अनारक्षित अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा लिखने का पात्र बन गया। यहां 'अनारक्षित' और 'आरक्षित' की बुनियादी संवैधानिक अवधारणा को समझना आवश्यक है। आरक्षण का उद्देश्य अवसरों से वंचित वर्गों को आगे बढ़ने का मंच देना है, न कि किसी मेधावी की योग्यता की अधिकतम सीमा तय करना। अनारक्षित श्रेणी कोई अलग सामाजिक वर्ग या जाति नहीं है, बल्कि यह एक खुली प्रतियोगिता है जहाँ मेरिट में आने वाला कोई भी योग्य अभ्यर्थी स्थान पाने का हकदार है। इस विधिक सिद्धांत को न्यायिक व्यवस्था ने समय-समय पर स्पष्ट और सुदृढ़ किया है। रजत यादव बनाम राजस्थान राज्य (उच्च न्यायालय) मामले में शीर्ष अदालत ने यह सिद्धांत दोहराया कि यदि किसी आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी, जिसने कोई विशेष रियायत नहीं ली है, सामान्य वर्ग के कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो उसे चयन के मध्यवर्ती व प्रारंभिक चरणों में भी खुली श्रेणी की मेरिट सूची में स्थान मिलना चाहिए। उसे केवल उसकी श्रेणी के नाम पर खुली प्रतिस्पर्धा से अलग-थलग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाम शाम कृष्णा बी में भी उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि आरक्षण रोस्टर और नियमों का मनमाना क्रियान्वयन मेधा को नकारने का माध्यम नहीं बन सकता; मेरिट में ऊपर रहने वाला आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में समायोजित होने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार रखता है। यह विसंगति पीसीएस जैसी बहु-चरणीय परीक्षाओं के प्रारंभिक स्तर पर सबसे घातक साबित होती है। यद्यपि प्रारंभिक परीक्षा के अंक अंतिम चयन सूची में नहीं जुड़ते, किंतु यह मुख्य परीक्षा तक पहुँचने का निर्णायक प्रवेश-द्वार है। यदि किसी अभ्यर्थी ने आयु सीमा या शुल्क जैसी कोई रियायत नहीं ली है और उसके अंक खुली श्रेणी के कटऑफ से अधिक हैं, तो उसे प्रारंभिक स्तर पर ही खुली प्रतियोगिता से बाहर कर देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित नैसर्गिक न्याय और समान अवसर के सिद्धांत के विपरीत है। अंतिम चरण में समायोजन का प्रावधान ऐसे मेधावी अभ्यर्थियों के लिए व्यर्थ सिद्ध होता है, क्योंकि वे मुख्य परीक्षा की दौड़ से ही बाहर कर दिए जाते हैं।

यह विवाद केवल ईडब्ल्यूएस तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आरक्षण के सभी वर्गों को प्रभावित करता है (जैसा कि वर्ष 2023 में ओबीसी वर्ग के 128 कटऑफ के साथ भी देखा गया)। यदि खुली सीटों पर केवल उन्हीं को प्रारंभिक प्रवेश मिलेगा जिन्होंने कोई आरक्षण क्लेम नहीं किया, तो 'अनारक्षित' सीटें वस्तुतः 'बिना आरक्षण वाले वर्ग' के लिए आरक्षित हो जाएंगी, जिससे खुली प्रतियोगिता की मूल आत्मा ही नष्ट हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस श्रेणी की पात्रता आर्थिक स्थिति से तय होती है, किंतु परीक्षा हॉल में उत्तर-पुस्तिका का मूल्यांकन अभ्यर्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि देखकर नहीं, बल्कि उसके ज्ञान और प्रदर्शन के आधार पर होता है। कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि किसी मेधावी छात्र के बेहतर प्रदर्शन की सीमा नहीं बननी चाहिए। जैसा कि न्यायशास्त्र का स्थापित नियम है—आरक्षण एक सुरक्षा-कवच है, प्रतिभा की छत नहीं। प्रतियोगी परीक्षाओं में व्यवस्था का सिद्धांत पारदर्शी और न्यायसंगत होना चाहिए—आरक्षण कमजोर को सहारा देने के लिए है, मेधावी के अवसर छीनने के लिए नहीं। ईडब्ल्यूएस होना किसी अभ्यर्थी की प्रतिभा का दायरा सीमित नहीं करता; यदि उसमें क्षमता है, तो खुली प्रतियोगिता का द्वार उसके लिए भी उतना ही खुला होना चाहिए जितना किसी अनारक्षित प्रतियोगी के लिए।

विचार

चेक बाउंस विवादों में तकनीक बने समाधान

डॉ. सुधीर कुमार

देश की अदालतों में करोड़ों लंबित मामलों में से एक-तिहाई से ज्यादा हिस्सेदारी अकेले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 यानी चेक बाउंस के मामलों की है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला अदालतों तक, चेक बाउंस के लाखों मामले लंबित हैं। कानूनी जानकारों का मानना है कि इनमें से अधिकांश विवाद वित्तीय लेन-देन से जुड़े असंतोष या छोटी-मोटी चूकों के कारण होते हैं। इसके बावजूद, एक साधारण-सा चेक बाउंस होने पर कानूनी नोटिस भेजने से लेकर अदालत में समन जारी होने, गवाही, जिरह और फैसले तक पहुंचने में वर्षों लग जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई मामलों में माना है कि इन मुकदमों का अंतहीन चलना व्यापारिक जगत और न्यायपालिका, दोनों के लिए घातक है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के दो महत्वपूर्ण और लैंडमार्क फैसले हैं। अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान लिए गए मामले 'इन री: एक्सपीडिशियस ट्रायल ऑफ केसेज अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट, 1881 (2020)' में बड़ी बेंच ने इस बात पर गंभीर चिंता जताई थी कि देश की अदालतों में चेक बाउंस के लाखों मामले लंबित हैं और इनका अंतहीन चलना न्याय व्यवस्था व व्यापारिक माहौल, दोनों के लिए घातक है। इसके साथ ही, 'दशरत रूपसिंह राठौड़ बनाम महाराष्ट्र' (2014) के ऐतिहासिक मामले में भी न्यायालय ने यह रेखांकित किया है कि पारंपरिक मुकदमेबाजी में वादी और प्रतिवादी, दोनों का धन, समय और मानसिक सुकून नष्ट होता है। न्यायालयों ने कई बार मध्यस्थता और त्वरित न्याय प्रणालियों पर जोर दिया है, क्योंकि जिस मामले को बैंक स्तर पर या चंद दिनों में सुलझाया जा सकता है, उसे वर्षों तक कचहरी के चक्कर कटवाए जाते हैं। इस स्थिति में हमें लीक से हटकर सोचना होगा और एक ऐसा क्रांतिकारी मॉडल अपनाना होगा, जो पूरी तरह तकनीक पर आधारित हो। यहां एक अनूठा और आधुनिक तरीका काम आ सकता है—'स्मार्ट-ब्रीच ऑटो-रेज़ोल्यूशन पोर्टल'। कल्पना कीजिए कि जैसे ही किसी व्यक्ति का चेक बैंक में अपर्याप्त राशि के कारण बाउंस होता है, पारंपरिक कागजी प्रक्रिया शुरू होने के बजाय एक स्वचालित डिजिटल ट्रिगर सक्रिय हो जाए। इस नए मॉडल के तहत, बैंक स्तर पर ही एक ऐसा स्मार्ट सॉफ्टवेयर काम करे, जो तुरंत संबंधित व्यक्ति के खाते से एक निश्चित डिजिटल पेनल्टी और मूल राशि का आंशिक या पूर्ण ट्रांसफर सुनिश्चित करे; बशर्ते दोनों पक्षों के बीच पहले से डिजिटल एग्रीमेंट हो।

यदि राशि को लेकर विवाद है, तो मामला सीधे कोर्ट जाने के बजाय ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म पर डायवर्ट हो जाए। ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक ऐसा वर्चुअल कोर्ट रूम या मध्यस्थता मंच है, जहां कोई वकील, कोई तारीख और कोई कागजी फाइल नहीं होती। दोनों पक्ष घर बैठे अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर के जरिए अपने दस्तावेज अपलोड करते हैं। एक प्रशिक्षित एआई-असिस्टेड मीडिएटर या डिजिटल एल्गोरिद्म दोनों पक्षों के डिजिटल रिकॉर्ड को खंगालकर 7 से 15 दिनों के भीतर एक बाध्यकारी समझौता प्रस्ताव तैयार कर देता है। यदि कोई पक्ष इसका उल्लंघन करता है, तो उसका क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड यानी सिबिल स्कोर स्वत: डाउन हो जाता है और उसके अन्य बैंक खातों पर स्वचालित डिजिटल होल्ड लग जाता है। यह तरीका न केवल अदालतों का बोझ कम करेगा, बल्कि आम आदमी को मानसिक तनाव से भी मुक्ति दिलाएगा। डिजिटल न्याय प्रणाली की सफलता के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी समझ, इंटरनेट और स्मार्टफोन की कमी जैसी व्यावहारिक बाधाओं को दूर करना आवश्यक है। ग्राम स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से डिजिटल हेल्प डेस्क बनाए जाने चाहिए, ताकि मुफ्त या कम शुल्क में तकनीकी सहायता मिल सके। जब तक डिजिटल साक्षरता और समावेशी मॉडल विकसित नहीं होंगे, तब तक न्याय का स्थानीयकरण अधूरा रहेगा। कानूनी ढांचे में दूरगामी बदलाव करते हुए सबसे पहले चेक बाउंस जैसे मामलों में प्री-लिटिगेशन मेडिएशन को अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिससे बैंक खाते से संदेश आते ही 15 दिनों की ऑनलाइन बातचीत के जरिए आधे से अधिक मामले अदालत पहुंचने से पहले ही सुलझ सकें। इसके साथ ही, कंपाउंडिंग यानी समझौते के नियमों का स्वत: क्रियान्वयन लागू होना चाहिए, ताकि आरोपी द्वारा डिजिटल माध्यम से मूल राशि व हर्जाना जमा करते ही, बिना अदालती चक्कर और जज की अनुमति के, मामला स्वत: समाप्त होकर सिस्टम से केस क्लोजर रिपोर्ट जारी हो सके। चेक बाउंस के मामलों में लोग जेल जाने के डर से भागते फिरते हैं या कानून की कमजोरियों का फायदा उठाकर वर्षों तक तारीखें लेते रहते हैं। हमें जेल भेजने की पुरानी ब्रिटिशकालीन मानसिकता से बाहर निकलकर कड़े वित्तीय दंड और दीर्घकालिक सिबिल पाबंदियों को सबसे बड़ा हथियार बनाना होगा।

एक नजर

औचक निरीक्षण में अल्ट्रासाउंड केंद्र सील, तकनीशियन द्वारा जांच करते पकड़ा गया

सुपौल,एजेंसी। जिले के किशनपुर प्रखंड में औचक निरीक्षण के क्रम में किशनपुर स्थित नेशनल अल्ट्रासाउंड सेंटर की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, किशनपुर भी मौके पर उपस्थित थे। जांच के क्रम में पाया गया कि केंद्र पर तकनीशियन द्वारा अल्ट्रासाउंड किया जा रहा था। मामले को गंभीरता से लेते हुए सिविल सर्जन, सुपौल के निर्देश पर संबंधित कर्मी के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की गई। साथ ही, नियमों के उल्लंघन के मद्देनजर नेशनल अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई के बाद अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संचालन एवं निर्धारित मानकों के अनुपालन को लेकर हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।एसडीएम मनोहर कुमार साहु ने बताया कि सील कर कार्रवाई की जा रही है।

एनएच-80 पर आफत की बाढ़, भागलपुर-पटना मार्ग पर आवागमन ठप

भागलपुर,एजेंसी। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर ने एक बार फिर जिले में विकराल रूप ले लिया है। भागलपुर के अकबरनगर और भवनाथपुर के बीच से गुजरने वाली मुख्य सड़क एन एच-80 पर बाढ़ का पानी करीब 2 से 3 फीट तक बह रहा है। भागलपुर को राजधानी पटना और सुल्तानगंज से जोड़ने वाले इस बेहद महत्वपूर्ण मार्ग पर पानी का बहाव इतना तेज है कि राहगीरों और वाहन चालकों की जान पर बन आई है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने दोगच्छी से अकबरनगर तक आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया है और फोरलेन वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने की सलाह दी है। सड़क पर पानी का स्तर लगातार बढ़ने के कारण दोपहिया और छोटे वाहन बीच रास्ते में ही बंद हो जा रहे हैं। पानी के तेज करंट के बीच गाड़ियों के बंद होने से दुर्घटनाओं का खतरा काफी बढ़ गया है और मार्ग पर भारी जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जरूरी कार्यों के लिए निकलने वाले स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर इसी जलमग्न सड़क से पैदल और नावों के सहारे आवागमन करने को मजबूर हैं। इस भयावह बाढ़ और संकट के बीच एन एच-80 पर एक बेहद हैरान करने वाला और अनोखा नजारा भी देखने को मिला। जहां एक तरफ लोग परेशान थे, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय बच्चों ने डूबी हुई सड़क को ही खेल का मैदान बना दिया। बच्चे जलमग्न हाईवे पर कमर तक पानी में खड़े होकर उत्साह के साथ वॉलीबॉल खेलते नजर आए। यह तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि बाढ़ ने जहां आम जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है, वहीं लोगों ने इस आपदा के बीच भी जीने का एक अलग रास्ता ढूंढ लिया है। बाढ़ के कारण भागलपुर-पटना का सड़क संपर्क पूरी तरह प्रभावित होने की कगार पर है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय नागरिकों और यात्रियों ने जिला प्रशासन से इस मार्ग पर तत्काल सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने, साइनबोर्ड लगाने और यातायात को पूरी तरह सुचारू करने के लिए वैकल्पिक प्रबंध करने की पुरजोर मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि जलस्तर में और वृद्धि हुई तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है।

भागलपुर में बाढ़ का महाखतरा 2021 के ऐतिहासिक जलस्तर से मात्र 6 सेमी दूर गंगा, बांधों पर बढ़ा दबाव

भागलपुर। जिले के गोपालपुर प्रखंड में गंगा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। नदी का जलस्तर अपने सर्वोच्च बाढ़ स्तर के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, जिससे पूरे इलाके में तबाही का खतरा मंडरा रहा है। बुधवार सुबह छह बजे इस्माईलपुर-बिंद टोली सुरक्षा बांध संख्या-7 पर गंगा का जलस्तर 33.44 मीटर दर्ज किया गया। जलसंसाधन विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 12 घंटों में नदी के जलस्तर में चार सेंटीमीटर की अप्रत्याशित बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस उछाल के बाद गंगा अब वर्ष 2021 में दर्ज किए गए अपने ऐतिहासिक सर्वोच्च बाढ़ स्तर (33.50 मीटर) से महज छह सेंटीमीटर नीचे बह रही है। स्थिति ठीक वैसी ही बनती जा रही है जैसी 2021 की विनाशकारी बाढ़ के समय थी, जिससे प्रशासनिक महकमे और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है। पानी की तेज रफ्तार और बढ़ते दबाव के कारण बांध संख्या-7 की स्थिति बेहद नाजुक है। इसके साथ ही क्षेत्र का अतिसंवेदनशील ब्रह्मोत्तर बांध भी खतरे में है। ब्रह्मोत्तर बांध के जिन हिस्सों पर तटबंध कमजोर हैं, वहां बाढ़ का पानी सीधे और भारी दबाव बना रहा है। जलसंसाधन विभाग के अभियंता और तकनीकी टीमें स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन पानी का थपेड़ा लगातार बांधों की मजबूती को चुनौती दे रहा है। गंगा के इस रौद्र रूप को देखकर तटवर्ती गांवों के निवासियों में संभावित कटाव और बाढ़ के डर से अफरा-तफरी का माहौल है। लोगों को डर है कि अगर बांध टूटा तो जान-माल का भारी नुकसान होगा। गोपालपुर के किसान रमेश मंडल ने अपनी चिंता साझा करते हुए कहा, 'सोचते हैं कि रात में बांध टूट गया तो क्या होगा? हमारे बच्चे, मवेशी, सब बह जाएंगे।'

बिहार के हित में फरक्का जल संधि पर पुनर्विचार जरूरी: संजय कुमार झा

पटना,एजेंसी। बिहार के खगड़िया जिले में जदयू के फरक्का जल संधि पर नीतीश संवाद कार्यक्रम का भव्य आयोजन बुधवार को किया गया। मौके पर खगड़िया के बछौता रोड स्थित शारदा फार्म हाउस में आयोजित भव्य कार्यक्रम में विधायक पन्ना लाल पटेल, विधायक बबलू मंडल, विधायक रामचन्द्र सदा, जिलाध्यक्ष अनुराधा कुमारी, प्रदेश महासचिव सह कार्यक्रम प्रभारी शंभू कुशवाहा, प्रदेश महासचिव सुनील कुमार, प्रदेश महासचिव सुमित कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कार्यक्रम के दौरान इस विषय पर पार्टी द्वारा तैयार की गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म खास तौर से दिखाई गई। साथ ही विस्तृत जानकारी वाला पम्फलेट भी बांटा गया। अपने संबोधन में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुई यह संधि भारत के, खासकर बिहार के हित में नहीं है, इसलिए इसका नवीनीकरण नहीं होना चाहिए और अगर कोई संधि होती भी है तो बिहार की वर्ष 2050 तक की जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस जल संधि के कारण बिहार का जल-प्रबंधन बुरी तरह बिगड़ा है और हम गंभीर जल-संकट का सामना कर रहे हैं। बिहार के हित में इस पर पुनर्विचार जरूरी है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कहा कि फरक्का (गंगा) जल संधि के मुताबिक शुष्क मौसम (1 जनवरी से 31 मई) में जब बक्सर के पास गंगा का प्रवाह महज 400 क्यूमेक (लगभग 14 हजार क्यूसेक) तक रह जाता है, तब भी फरक्का से बांग्लादेश के लिए 1500 क्यूमेक (लगभग 53 हजार क्यूसेक) पानी छोड़ना पड़ता है, इसका मतलब यह है कि सिर्फ गंगा ही नहीं, बल्कि बिहार की आंतरिक नदियों से भी पानी खींचकर बांग्लादेश को दिया जा रहा है। यह सीधे तौर पर बिहार की हकमारी है। उन्होंने कहा कि बिहार और केन्द्र की तत्कालीन सरकार में बैठे लोगों ने बिहार के हितों की बलि चढ़ा दी। उन लोगों ने यह नहीं सोचा कि ऐसा करके वे बिहार के किसानों की सिंचाई, लोगों का पेयजल, उद्योगों की पानी की जरूरत, लाखों लोगों की आजीविका और राज्य के युवाओं का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं।

प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि हमारे सर्वमान्य नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार शुरू से कहते रहे हैं कि फरक्का बराज और फरक्का जल संधि से बिहार को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक ओर फरक्का बराज के कारण गंगा में भारी गाद जमा हो जाने से नदी का तल ऊँचा हो गया है, जिसके कारण उत्तर बिहार को हर साल बाढ़ का सामना करना पड़ता है, तो दूसरी ओर फरक्का जल संधि के कारण शुष्क मौसम में हमें बिहार के हिस्से का पानी बांग्लादेश को देना पड़ता है और हमारे कई जिलों में सूखे तक की स्थिति हो जाती है। उन्होंने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय संधि का 73 प्रतिशत बोझ अकेले बिहार उठा रहा है और 30 वर्षों से एक साथ बाढ़ और सूखे का दंश झेल रहा है। यह हमारे साथ ज्यादती है, जिसे हम इस अभियान के माध्यम से बताना चाहते हैं। उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि मैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ी मुखरता से इस विषय को उठाया।

विवाह के 5 दिन बाद ही नवविवाहिता को पति ने छोड़ा, ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप, न्याय के लिए मानवाधिकार संस्था पहुंची पीड़िता

भागलपुर। ससुराल में उत्पीड़न और पुलिसिया कार्रवाई में ढील से परेशान एक पीड़िता न्याय की गुहार लेकर बुधवार को राष्ट्र मानवाधिकार संस्था के कार्यालय पहुंची। पीड़िता की दो-तीन मुस्लिम महिला बहनें संस्था के कार्यालय में उपस्थित हुईं और अपनी छोटी बहन के साथ हो रहे घोर अत्याचार और मानसिक प्रताड़ना की लिखित शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित परिवार मूल रूप से भागलपुर के मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र का निवासी है। आवेदन के अनुसार, पीड़िता का निकाह बड़े ही धूमधाम से हुआ था, जिसमें लड़की वालों की तरफ से शादी के खर्च के नाम पर लड़के के खाते में लगभग 3,00,000 (तीन लाख रुपये) ट्रांसफर किए गए थे।

इसके अतिरिक्त बर्तन, पलंग, अलमीरा सहित तमाम जरूरी घरेलू सामान (दहेज सामग्री) भी उपहार स्वरूप दिए गए थे लेकिन शादी के महज 5 से 6 दिन बाद ही पति नवविवाहिता को छोड़कर कहीं चला गया। पति के जाते ही ससुराल में सास, ससुर और ननद पीड़िता को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। ससुराल वालों के जुल्म से तंग आकर पीड़िता ने फुलवारी शरीफ थाना में लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता के पास बैंक ट्रांजैक्शन और शादी के सामान की पक्की रसीदें समेत तमाम पुख्ता प्रमाण थे, जो पुलिस को सौंप दिए गए थे। बावजूद इसके, काफी समय बीतने के बाद भी फुलवारी शरीफ पुलिस द्वारा कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं की गई और मामला जस का तस बना रहा। पुलिस के इस ढुलमुल रवैए से परेशान होकर आखिरकार पीड़िता की बहनों ने मानवाधिकार संगठन का दरवाजा खटखटाया। मामले को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्र मानवाधिकार संस्था के अध्यक्ष ईशान सिन्हा ने तुरंत फुलवारी शरीफ थाना प्रभारी से फोन पर बात की और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली।

मानवाधिकार संस्था के हस्तक्षेप के बाद फुलवारी शरीफ थानाध्यक्ष ने मामले में निष्पक्ष न्याय का पूर्ण आश्वासन दिया है। थानाध्यक्ष ने संवेदनशीलता दिखाते हुए दोनों पक्षों को थाने बुलाकर समस्या का उचित समाधान निकालने की बात कही है। अब देखना यह है कि इस बेसहारा पीड़ित महिला को कब तक इंसाफ मिल पाता है। राष्ट्र मानवाधिकार संस्था ने उम्मीद जताई है कि थानाध्यक्ष मामले की गंभीरता को समझते हुए उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे और पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाकर मामले का सही निपटारा करेंगे।

दिनदहाड़े ज्वेलरी दुकान में लूट का प्रयास, विरोध करने वाले दुकानदार की मौत

सीवान। जिले के दरौली थाना क्षेत्र के टड़वा परसिया बाजार में मंगलवार को दिनदहाड़े नीरज ज्वेलर्स में हुई लूट की कोशिश अब हत्या में बदल गयी है। अपराधियों के हमले में गंभीर रूप से घायल स्वर्ण व्यवसायी दिलीप वर्मा की बुधवार को इलाज के दौरान देवरिया में मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। वहीं, दिनदहाड़े हथियारबंद अपराधियों के दुस्साहस ने बाजार की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंगलवार की दोपहर करीब 1:30 बजे दो बाइक पर सवार करीब छह अपराधी टड़वा परसिया बाजार पहुंचे थे।इनमें से चार हथियारों से लैस होकर नीरज ज्वेलर्स में घुसे और शटर गिराकर लूटपाट शुरू कर दी। दुकान में मौजूद स्वर्ण व्यवसायी दिलीप वर्मा ने अपराधियों का विरोध किया। विरोध के दौरान अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया। इसके बावजूद दिलीप वर्मा ने हिम्मत नहीं हारी और एक अपराधी को पकड़ लिया। इसी दौरान दुकान के बाहर लोगों को गोली चलने की आवाज सुनाई दी। अपराधियों ने शटर खोलकर भागने का प्रयास किया। भागते समय अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर पूरे बाजार में दहशत कायम कर दी। अचानक हुई गोलीबारी से बाजार में अफरातफरी मच गयी और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने भाग रहे एक अन्य अपराधी को पकड़ लिया। घटना की सूचना मिलते ही दरौली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पकड़े गये आरोपितों को हिरासत में ले लिया। वहीं, अन्य अपराधी मौके से फरार होने में सफल रहे। पुलिस ने पकड़े गये आरोपितों से पूछताछ शुरू कर दी है। गंभीर रूप से घायल दिलीप वर्मा को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए देवरिया रेफर कर दिया। वहां इलाज के दौरान बुधवार को उनकी मौत हो गयी. उनकी मौत की खबर मिलते ही बाजार में शोक के साथ लोगों का आक्रोश भी बढ़ गया। घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया और टड़वा परसिया बाजार में पुलिस थाना खोलने की मांग की। लोगों का कहना था कि बाजार में दिनदहाड़े हथियारबंद अपराधियों द्वारा ज्वेलरी दुकान को निशाना बनाना और भागने के दौरान खुलेआम फायरिंग करना पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। एसपी भारत सोनी के निर्देश पर एसडीपीओ सदर-2 के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है।

नालंदा जिले के नगरनौसा में गोदाम से 7.471 किलो गांजा जैसा मादक पदार्थ बरामद, तीन गिरफ्तार

नालंदा, बिहारशरीफ। नालंदा जिले के नगरनौसा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गोदाम में छापेमारी कर 7.471 किलोग्राम गांजा जैसा मादक पदार्थ बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। उनके पास से 3.70 लाख रुपये नकद, दो मोटरसाइकिल और तस्करी में प्रयुक्त एक मारुति ऑल्टो कार भी जब्त की गई है। नगरनौसा थाना पुलिस ने बताया कि 7 सितंबर 2026 की शाम गश्ती के दौरान सूचना मिली थी कि नगरनौसा थाना क्षेत्र के बदल बिगहा गांव स्थित संजय श्रीवास्तव के गोदाम में अवैध मादक पदार्थ छिपाकर रखा गया है और उसका कारोबार किया जा रहा है।

सूचना के सत्यापन के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, हिलसा-01 के नेतृत्व में नगरनौसा थाना पुलिस की टीम ने आज बुधवार को गोदाम की घेराबंदी कर विधिवत तलाशी और छापेमारी की।तलाशी के दौरान गोदाम के पश्चिमी हिस्से में भूसा रखे बोरों के ढेर के पास लाल रंग के चोकर के बोरे में छिपाकर रखा 7.471 किलो गांजा जैसा मादक पदार्थ बरामद किया गया। वहीं, गोदाम के पूर्वी हिस्से के एक कमरे से थैले में रखे 3,70,000 रुपये नकद बरामद किए गए, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है।छापेमारी के दौरान पुलिस ने संजय श्रीवास्तव और दीनानाथ प्रसाद के पास से दो मोबाइल फोन भी बरामद किया है। इसके अलावा गोदाम के बाहर मादक पदार्थ की बिक्री में इस्तेमाल किए जाने वाले दो मोटरसाइकिल—हीरो स्प्लेंडर प्लस और होंडा एसपी-125—को जब्त किया गया है। पुलिस ने दीनानाथ प्रसाद से पूछताछ के आधार पर मामले में शामिल बताए जा रहे सुबोध कुमार को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, सुबोध कुमार की निशानदेही पर तस्करी में प्रयुक्त मारुति ऑल्टो कार (BR-1AG-6885) बरामद की गई।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संजय श्रीवास्तव (42), दीनानाथ प्रसाद (30) और सुबोध कुमार (50) के रूप में हुई है। तीनों नगरनौसा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं।इस मामले में नगरनौसा थाना कांड संख्या 221/26, दिनांक 08 सितंबर 2026 दर्ज कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20(b)(ii)(B)/25/29 के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार तीनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की प्रक्रिया की जा रही है।छापेमारी टीम में नगरनौसा थानाध्यक्ष पुअनि शशिरंजन कुमार मिश्रा, पुअनि संदीप कुमार सिंह, पुअनि सुदेश्वर राय समेत थाना के पुलिसकर्मी और जवान शामिल रहे। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के कारोबार के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।

नाथनगर में बाढ़ का तांडव, स्कूल डूबे, गांवों का संपर्क टूटा, घुटने भर पानी में जाने को मजबूर नौनिहाल

भागलपुर,एजेंसी। जिले के नाथनगर प्रखंड में बाढ़ का संकट दिन-ब-दिन गहराता जा रहा है। गंगा और सहायक नदियों के लगातार बढ़ रहे जलस्तर के कारण प्रखंड की कई पंचायतें टापू में तब्दील हो गई हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि बेलखुरिया पंचायत स्थित मध्य विद्यालय और भुवालपुर पंचायत का पुरानी सराय गाँव पूरी तरह बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। पूरे इलाके में जलजमाव के कारण आम जनजीवन बुरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है और ग्रामीणों को कठिन परिस्थितियों में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। बेलखुरिया पंचायत का मध्य विद्यालय बेलखुरिया इस समय चारों तरफ से पानी से घिर चुका है। स्कूल परिसर में घुटने तक पानी जमा है।

हैरान करने वाली बात यह है कि इस जानलेवा खतरे के बावजूद छात्र-छात्राएं कंधे पर स्कूल बैग टांगे, इसी गंदे और गहरे पानी से होकर कक्षा तक जाने को मजबूर हैं। स्कूल भवन और आसपास का इलाका बुरी तरह प्रभावित होने से बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों और स्थानीय लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पानी लगातार बढ़ रहा है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उधर, भुवालपुर पंचायत के पुरानी सराय गाँव की स्थिति भी बदतर हो गई है। पूरा गाँव बाढ़ के पानी के घेरे में है। गाँव की अंदरूनी गलियों से लेकर मुख्य सड़कों पर कई फीट पानी बह रहा है, जिसके कारण वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। जलजमाव का असर लोगों के चूल्हे-चौके पर भी पड़ने लगा है। राशन, दवा और दूध जैसे जरूरी सामान लाने के लिए ग्रामीणों को पानी के बीच से ही पैदल गुजरना पड़ रहा है। गाँव में फंसे बुजुर्गों, महिलाओं और बीमार लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। बाढ़ की इस विभीषिका के बीच स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति गहरा आक्रोश है। प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि पानी का जलस्तर हर घंटे बढ़ रहा है, लेकिन अब तक प्रशासनिक अधिकारियों ने इलाके का जायजा नहीं लिया है। लोगों ने माँग की है कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए तत्काल प्रभाव से प्रभावित स्कूलों में पढ़ाई की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए अथवा अवकाश घोषित किया जाए। साथ ही, पुरानी सराय सहित अन्य जलमग्न गाँवों में सुरक्षित आवागमन के लिए सरकारी नावों की व्यवस्था की जाए और राहत शिविर चलाए जाएं। अब देखना यह है कि सो रहा जिला प्रशासन प्रभावित लोगों को राहत पहुँचाने के लिए कब जागता है।

नालंदा जिले में कॉल फॉरवर्डिंग कर व्हाट्सऐप हैक कर परिचितों से पैसे मांगने वाले दो साइबर ठग गिरफ्तार

नालंदा, बिहारशरीफ। नालंदा में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने आज बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए कॉल फॉरवर्डिंग के जरिए लोगों के व्हाट्सऐप तक पहुंच बनाकर उनके परिचितों से पैसे की मांग करने वाले दो साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने आठ स्क्रीन टच मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दोनों आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

अस्थावां थाना पुलिस ने बताया कि अस्थावां थाना क्षेत्र के गोठिया गांव में कुछ लोगों द्वारा साइबर ठगी किए जाने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर नालंदा साइबर थाना की टीम ने गोठिया गांव स्थित मुर्गी फार्म और कुछ संदिग्ध लोगों के घरों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने संदिग्धों से पूछताछ की, जिसमें साइबर ठगी के तरीके का खुलासा हुआ।जांच में सामने आया कि आरोपी खुद को ब्लूडार्ट का एजेंट बताकर लोगों से संपर्क करते थे। पार्सल डिलीवरी के नाम पर वे लोगों को फोन करते और किसी दूसरे नंबर पर कॉल करने या मोबाइल में एक विशेष कोड डायल करने के लिए कहते थे। इसके बाद आरोपी पीड़ित के मोबाइल में कॉल फॉरवर्डिंग सक्रिय कर देते थे।कॉल फॉरवर्डिंग सक्रिय होने के बाद आरोपी पीड़ित के परिचितों से संपर्क करते थे। उन्हें बताया जाता था कि संबंधित व्यक्ति किसी आपात स्थिति या संकट में फंस गया है और उसे तत्काल पैसों की जरूरत है। इस तरह परिचितों को झांसे में लेकर उनके जरिए पैसे की मांग की जाती थी।

पुलिस ने इस मामले में नालंदा साइबर थाना में कांड संख्या 211/26, के तहत एक मामला दर्ज किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ विधिवत कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोहन पटेल (26 वर्ष), पिता रविशंकर प्रसाद तथा मनीष कुमार (23 वर्ष), पिता अनिल प्रसाद के रूप में हुई है। दोनों गोठिया गांव, थाना अस्थावां, जिला नालंदा के रहने वाले बताए गए हैं।छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से आठ स्क्रीन टच मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस बरामद मोबाइल की तकनीकी जांच कर रही है। जांच के दौरान साइबर ठगी से जुड़े अन्य मामलों और गिरोह में शामिल लोगों के बारे में भी जानकारी मिलने की संभावना है।इस कार्रवाई में नालंदा साइबर थाना के पु0अ0नि0 अबू तालीब अंसारी, तौकीर खान कुमार और विवेक कुमार के अलावा सिपाही पुनेश कुमार, यश कुमार, चंदन कुमार, रविनंदन कुमार, रवि कुमार, चालक सिपाही निरंजन कुमार तथा गृह रक्षक करण कुमार शामिल रहे। कार्रवाई में जिला आसूचना इकाई की टीम का भी सहयोग रहा।नालंदा पुलिस ने आम लोगों से साइबर अपराधियों से सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस ने कहा कि फोन कॉल, व्हाट्सऐप कॉल, एसएमएस या विज्ञापन के माध्यम से मिलने वाली किसी भी सूचना पर बिना सत्यापन के भरोसा नहीं करें।

बैलन डी 'ओर 2026 : मेसी, एमबापे, यामाल और केन समेत 30 खिलाड़ी नामित

पेरिस, एजेंसी। फ्रांस की फुटबॉल पत्रिका 'फ्रांस फुटबॉल' ने मंगलवार को बैलन डी 'ओर 2026 पुरस्कारों के लिए विभिन्न श्रेणियों में नामित खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों की सूची जारी कर दी। पुरुष वर्ग में फ्रांस के किलियन एमबापे, स्पेन के लामिन यामाल, इंग्लैंड के हैरी केन और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी समेत 30 खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। पुरुष बैलन डी 'ओर के नामांकन में फीफा विश्व कप विजेता स्पेन और यूईएफए चैंपियंस लीग विजेता पेरिस सेंट-जर्मेन के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। पिछले साल के विजेता उस्मान डेम्बेले को भी लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार जीतने का मौका मिलेगा। डेम्बेले ने पेरिस सेंट-जर्मेन के साथ लगातार दूसरा चैंपियंस लीग खिताब जीता है। एमबापे, लामिन यामाल और हैरी केन को प्रमुख दावेदारों में माना जा रहा है। वहीं, लियोनेल मेसी ने विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के दम पर नामांकन हासिल किया है।

पुरुष बैलन डी 'ओर 2026 के नामित खिलाड़ी:

जूड बेलिंगहैम (इंग्लैंड/रियल मैड्रिड), पाउ कुबार्सी (स्पेन/बार्सिलोना), मार्क कुकुरेला (स्पेन/रियल मैड्रिड), उस्मान डेम्बेले (फ्रांस/पेरिस सेंट-जर्मेन), लुइस डियाज (कोलंबिया/बायर्न म्यूनिख), ब्रूनो फर्नांडिस (पुर्तगाल/मैनचेस्टर यूनाइटेड), एर्लिंग हालांड (नॉर्वे/मैनचेस्टर सिटी), गेब्रियल मागाल्हाएस (ब्राजील/आर्सेनल), हैरी केन (इंग्लैंड/बायर्न म्यूनिख), अचरफ हकीमी (मोरक्को/पेरिस सेंट-जर्मेन), लामिन यामाल (स्पेन/बार्सिलोना), ख्विचा क्वारात्सखेलिया (जॉर्जिया/पेरिस सेंट-जर्मेन), मार्किन्होस (ब्राजील/पेरिस सेंट-जर्मेन), सादियो माने (सेनेगल/अल-नस्र), लाउतारो मार्टिनेज (अर्जेंटीना/इंटर मिलान), किलियन एमबापे (फ्रांस/रियल मैड्रिड), लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना/इंटर मियामी), माइकल ओलिसे (फ्रांस/बायर्न म्यूनिख), जोआओ नेवेस (पुर्तगाल/पेरिस सेंट-जर्मेन), विलियन पाचो (इक्वाडोर/पेरिस सेंट-जर्मेन), जूलियन क्विनोनेस (मैक्सिको/अल-कादसियाह), डेक्लान राइस (इंग्लैंड/आर्सेनल), रोड्री (स्पेन/बार्सिलोना), फैबियन रुइज (स्पेन/पेरिस सेंट-जर्मेन), विलियम सालिबा (फ्रांस/आर्सेनल), दयोट उपामेकानो (फ्रांस/बायर्न म्यूनिख), विटिन्या (पुर्तगाल/पेरिस सेंट-जर्मेन), फेरान टोरेस (स्पेन/पेरिस सेंट-जर्मेन), विनिसियस जूनियर (ब्राजील/रियल मैड्रिड) और नूनो मेंडेस (पुर्तगाल/पेरिस सेंट-जर्मेन)।

पुरुष कोच ऑफ द ईयर के नामित:

मिकेल आर्टेटा (आर्सेनल), लुइस दे ला फुएंते (स्पेन), उनाई एमरी (एस्टन विला), विन्सेंट कोम्पनी (बायर्न म्यूनिख) और लुइस एनरिके (पेरिस सेंट-जर्मेन)। महिला वर्ग में दो बार की विजेता एलेक्सिया पुतायस, ईवा पायजोर और मेल्ची डुमोर्नाय प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों की विजेता ऐताना बोनमती चोट के कारण अधिकांश सत्र से बाहर रहने की वजह से इस बार नामांकित नहीं की गई हैं।

महिला बैलन डी 'ओर 2026 के नामित खिलाड़ी:

सेल्मा बाचा (ओएल ल्योन), बारबरा बांडा (ऑरलैंडो प्राइड), क्लारा ब्यूल (बायर्न म्यूनिख), एस्मी ब्रुग्ट्स (बार्सिलोना), मारियोना काल्डेंते (आर्सेनल), स्कारलेट कंबेरोस (क्लब अमेरिका), केर्स्टिन कास्पारिज (मैनचेस्टर सिटी), टेम्वा चाविंगा (कैनसस सिटी करंट), काटा कोल (बार्सिलोना), मेल्ची डुमोर्नाय (ओएल ल्योन), कैरोलीन ग्राहम हैनसन (बार्सिलोना), एलेक्स ग्रीनवुड (मैनचेस्टर सिटी), पैट्री गुइजारो (बार्सिलोना), पेर्निले हार्डर (बायर्न म्यूनिख), युई हासेगावा (मैनचेस्टर सिटी), रोज लावेल (गॉथम एफसी), मापी लियोन (लंदन सिटी लायनेसिस), लोरेना (कैनसस सिटी करंट), मेलविन मलार्ड (चेल्सी), मनाका मात्सुकुबो (चेल्सी), विवियाने मिएदेमा (मैनचेस्टर सिटी), ईवा पायजोर (बार्सिलोना), क्लाउडिया पिना (बार्सिलोना), एलेक्सिया पुतायस (लंदन सिटी लायनेसिस), वेंडी रेनार्ड (ओएल ल्योन), एलेसिया रूसो (आर्सेनल), खदीजा शॉ (मैनचेस्टर सिटी), मोमोको तनिकावा (बायर्न म्यूनिख), कैरोलिन वियर (ओएल ल्योन) और टेसा वुलार्ट (कोमो)।

महिला कोच ऑफ द ईयर के नामित:

जोनाथन गिराल्देज (ओएल ल्योन), आंद्रे येगर्ट्ज (मैनचेस्टर सिटी), निल्स नील्सन (जापान), पेरे रोम्यू (बार्सिलोना) और एलेना सादिकु (बीके हेकन)। युवा खिलाड़ियों के लिए पुरुष कोपा ट्रॉफी के नामांकन में केरिम अलाजबेगोविच, अय्यूब बुआद्दी, पाउ कुबार्सी, यान डियोमांदे, लेनार्ट कार्ल, एली जूनियर क्रुपी, लामिन यामाल, जोहान मांजांबी, इब्राहिम माजा और वॉरेन जायरे-एमरी शामिल हैं। महिला कोपा ट्रॉफी के लिए वीरले बुरमान, विक्की लोपेज, फेलिसिया श्रोडर, क्लारा सेर्राजोर्डी और लिली योहानेस को नामांकित किया गया है।

याशिन ट्रॉफी के लिए पुरुष गोलकीपरों के नामित:

यासीन बूनू (अल हिलाल), जोआन गार्सिया (बार्सिलोना), ग्रेगोर कोबेल (बोरूसिया डॉर्टमुंड), एमिलियानो मार्टिनेज (चेल्सी), एडुआर्ड मेंडी (अल अहली), डेविड राया (आर्सेनल), उनाई सिमोन (एथलेटिक बिलबाओ), वोजिन्हा (कोलो-कोलो), मतवे साफोनोव (पेरिस सेंट-जर्मेन) और थिबो कोर्टुआ (रियल मैड्रिड)।

महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर के नामित:

हन्ना हैम्पटन (चेल्सी), लोरेना (कैनसस सिटी करंट), आयाका यामाशिता (मैनचेस्टर सिटी), काटा कोल (बार्सिलोना) और एन-कैटरीन बर्गर (गॉथम एफसी)।

2026 पुरुष टीम ऑफ द ईयर के नामित:

आर्सेनल, बायर्न म्यूनिख, बोदो/ग्लिम्ट, फ्लामेंगो और पेरिस सेंट-जर्मेन।

2026 महिला टीम ऑफ द ईयर के नामित:

एफसी बार्सिलोना, बायर्न म्यूनिख, क्लब अमेरिका, मैनचेस्टर सिटी और ओलंपिक ल्योन। बैलन डी 'ओर पुरस्कार समारोह 26 अक्टूबर को लंदन में आयोजित किया जाएगा। पुरुषों के लिए यह पुरस्कार 1956 से और महिलाओं के लिए 2018 से प्रदान किया जा रहा है। पुरुष वर्ग के विजेता का चयन फीफा रैंकिंग में शीर्ष 100 देशों के पत्रकारों और महिला वर्ग के विजेता का चयन शीर्ष 50 रैंकिंग वाले देशों के पत्रकारों के मतदान से किया जाता है।

एक नजर

विश्व पैरा तीरंदाजी सीरीज : शीतल देवी ने कंपाउंड में जीता स्वर्ण, हरविंदर-भावना की जोड़ी भी बनी चैंपियन

अहमदाबाद, एजेंसी। भारत की युवा तीरंदाज शीतल देवी ने बुधवार को विश्व पैरा तीरंदाजी सीरीज-2026 में महिला कंपाउंड स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया। शीतल ने फाइनल में कजाकिस्तान की आइजादा सेइदान को शूट-ऑफ में 10-9 से हराकर स्वर्ण अपने नाम किया। निर्धारित मुकाबले में दोनों तीरंदाजों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला और स्कोर 144-144 से बराबर रहा। इसके बाद मुकाबला शूट-ऑफ में पहुंचा, जहां शीतल ने 10-9 से बाजी मारते हुए खिताब अपने नाम किया। भारत के हरविंदर सिंह और भावना की जोड़ी ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए रिकर्व मिश्रित टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में चीन की लियांग च्यूरोंग और शिया लेई को 6-0 से एकतरफा अंदाज में हराया। महिला रिकर्व स्पर्धा में भी भारत के खाते में पदक आया। कांस्य पदक के लिए हुए ऑल-इंडियन मुकाबले में भावना ने राजश्री राठौड़ को 6-0 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुष कंपाउंड स्पर्धा में भी भारतीय दल को एक और पदक मिला। चौथी वरीयता प्राप्त तोमन कुमार ने इराक के अब्बास काधिम को 143-138 से हराकर कांस्य पदक जीता। इस तरह विश्व पैरा तीरंदाजी सीरीज 2026 में भारत ने कंपाउंड और रिकर्व दोनों वर्गों में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम किए।

वियतनाम ओपन : तन्वी शर्मा ने रेचल चैन को सीधे गेमों में हराया, अगले दौर में पहुंचीं

हो ची मिन्ह सिटी। शीर्ष वरीय भारतीय खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने बुधवार को वियतनाम ओपन 2026 के महिला एकल के अंतिम-32 मुकाबले में कनाडा की रेचल चैन को सीधे गेमों में 21-16, 21-17 से हराकर अगले दौर में जगह बना ली। बीएफडब्ल्यू विश्व टूर सुपर 100 प्रतियोगिता में तन्वी ने 36 मिनट में मुकाबला अपने नाम किया। भारतीय किशोरी ने पूरे मैच में दबदबा बनाए रखा और लगातार दो गेम जीतकर अंतिम-16 में प्रवेश किया। तन्वी इस महीने की शुरुआत में चाइना मास्टर्स 2026 में जापान की विश्व नंबर-9 टोमोका मियाजाकी के खिलाफ 66 मिनट चले रोमांचक मुकाबले में 17-21, 21-18, 16-21 से हारकर अंतिम-16 में बाहर हो गई थीं। इससे पहले उन्होंने डेनमार्क की अमाली शुल्ज को 21-16, 21-17 से हराकर अंतिम-16 में जगह बनाई थी। पिछले महीने तन्वी ने ताइपे ओपन सुपर 300 में अपना पहला बीएफडब्ल्यू विश्व टूर खिताब जीता था। उन्होंने महिला एकल के फाइनल में वियतनाम की छठी वरीय गुयेन थुई लिन्ह को 21-16, 21-16 से हराया था। इस जीत के साथ वह 2008 में साइना नेहवाल के बाद ताइपे ओपन महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी थीं। पार्क ताए-सांग के मार्गदर्शन में खेल रही तन्वी पिछले साल यूएस ओपन सुपर 300 में उपविजेता रही थीं। पार्क ताए-सांग पूर्व में पीवी सिंधु के प्रशिक्षक भी रह चुके हैं। वियतनाम ओपन में बुधवार को एक अन्य भारतीय अनमोल खरब को थाईलैंड की सारुनराक वितिदसार्न ने 21-14, 21-14 से हराया। वहीं, आलाप मिश्रा ने हमवतन आर्या भविपाठकी को 21-8, 21-14 से मात दी।

महिला जूनियर एशिया कप में भारत ने चीन को गोलरहित रोका, एलीट पूल में शीर्ष पर

मोगी (चीन)। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने बुधवार को महिला जूनियर एशिया कप के एलीट पूल के अंतिम मुकाबले में मेजबान चीन को गोलरहित बराबरी पर रोक दिया। इस परिणाम के साथ भारत तीन जीत और एक ड्रॉ से 10 अंक जुटाकर पूल में शीर्ष पर रहा। बेहतर गोल अंतर के आधार पर भारत ने चीन को पीछे छोड़ा। चीन ने मुकाबले की शुरुआत आक्रामक अंदाज में की और भारतीय रक्षापंक्ति पर लगातार दबाव बनाया। मेजबान टीम को शुरुआती पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार बचाव किया। पहले क्वार्टर में चीन को पेनल्टी स्ट्रोक भी मिला, लेकिन भारतीय गोलकीपर निधि ने बेहतरीन बचाव करते हुए खतरा टाल दिया। इसके बाद भारत ने भी आक्रमण तेज किया और कई मौके बनाए। हालांकि, चीन की संगठित रक्षापंक्ति ने भारतीय हमलों को रोक दिया। दूसरे क्वार्टर में दोनों टीमों को पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन कोई भी उन्हें गोल में नहीं बदल सकी। मध्यांतर तक स्कोर 0-0 रहा। तीसरे क्वार्टर में भी दोनों टीमों के बीच बराबरी का मुकाबला देखने को मिला। भारत की रक्षा पंक्ति ने चीन के हमलों को प्रभावी ढंग से रोका, जबकि भारतीय टीम ने भी जवाबी हमलों के जरिए मौके बनाए। अंतिम क्वार्टर में दोनों टीमों ने निर्णायक गोल के लिए प्रयास किए, लेकिन कोई भी रक्षा को भेदने में सफल नहीं रही।

ड्रॉ के साथ भारत और चीन दोनों के खाते में एक-एक अंक जुड़ा और दोनों के 10 अंक रहे। बेहतर गोल अंतर के कारण भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया। अब भारतीय टीम 10 सितंबर को क्वार्टर फाइनल-1 में पाकिस्तान से भिड़ेगी। पाकिस्तान चैलेंजर पूल में चार मैचों से सात अंक लेकर तीसरे स्थान पर रहा। भारतीय टीम टूर्नामेंट में अपना अजेय अभियान जारी रखते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाने के इरादे से उतरेगी।

यूएस ओपन: जेसिका पेगुला ने एम्मा नवारो को हराया, सेमीफाइनल में सबालेंका से होगी भिड़ंत

न्यूयॉर्क। तीसरी वरीयता प्राप्त अमेरिकी खिलाड़ी जेसिका पेगुला ने मंगलवार को यूएस ओपन 2026 के महिला एकल क्वार्टर फाइनल में हमवतन एम्मा नवारो को 3-6, 6-4, 6-3 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। अब उनका सामना दो बार की गत चैंपियन आर्यना सबालेंका से होगा। पेगुला ने दो घंटे 20 मिनट चले मुकाबले में शुरुआती सेट गंवाने के बाद शानदार वापसी की। तीसरे सेट में शुरुआती ब्रेक से पिछड़ने के बावजूद उन्होंने वापसी की और कड़े बेसलाइन मुकाबले में जीत हासिल की। दोनों खिलाड़ियों के बीच मुकाबले में कुल नौ बार सर्विस ब्रेक हुई। जीत के बाद पेगुला ने ऑन कोर्ट साक्षात्कार में कहा, 'यह वास्तव में बहुत कठिन था। मुकाबला शारीरिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण था और मौसम भी उमस भरा था। मैं अपनी सर्विस से बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी और आज मुझे कोर्ट पर काफी संघर्ष करना पड़ा।'

इस जीत के साथ पेगुला का नवारो के खिलाफ रिकॉर्ड 5-0 हो गया है। पूर्व विश्व नंबर आठ नवारो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देने के लिए लंबे ब्रेक के बाद वापसी कर रही हैं। उन्होंने मई में स्ट्रासबर्ग में एक साल से अधिक समय बाद अपना पहला खिताब जीता था। पेगुला ने इस साल अब तक दो खिताब जीते हैं और

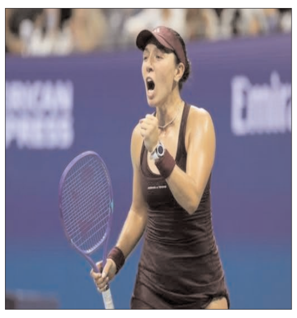

वह उन तीन खिलाड़ियों में शामिल हैं, जो न्यूयॉर्क में विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर काबिज सबालेंका को पीछे छोड़ने की दौड़ में थीं। हालांकि, शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए 32 वर्षीय पेगुला को अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतना होगा। पेगुला और सबालेंका के बीच यूएस ओपन में यह लगातार तीसरा मुकाबला होगा। सबालेंका ने 2024 के फाइनल में पेगुला को हराकर खिताब जीता था और पिछले साल सेमीफाइनल में भी उन्हें मात देकर लगातार दूसरा यूएस ओपन खिताब अपने नाम किया था। दोनों के बीच गुरुवार को होने वाला सेमीफाइनल हालांकि विश्व रैंकिंग के शीर्ष स्थान की तस्वीर बदलने से पहले ही अपना महत्व खो सकता है। दूसरे स्थान पर काबिज एलेना राइबाकिना बुधवार को चीन की झेंग छिनवेन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल जीतते ही अन्य नतीजों की परवाह किए बिना विश्व नंबर एक बन जाएंगी।

यूएस किड्स गोल्फ इंडिया सीरीज का छठा सत्र शुरू, युवा खिलाड़ियों की नजर अंतरराष्ट्रीय मंच पर

गुरुग्राम, एजेंसी। यूएस किड्स गोल्फ इंडिया सीरीज अपने छठे सत्र के साथ लौट आई है। 50 से अधिक युवा गोल्फर 11 और 12 सितंबर को क्लासिक गोल्फ एंड कंट्री क्लब में विभिन्न आयु वर्गों में मुकाबला करेंगे। सीरीज का उद्देश्य भारतीय जूनियर खिलाड़ियों को घरेलू प्रतियोगिताओं से अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का अवसर उपलब्ध कराना है। भारत में यूएस किड्स गोल्फ की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इसका असर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों की भागीदारी और प्रदर्शन में भी देखने को मिला है। 2026 यूएस किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में निहाल चीमा ने बॉयज-9 वर्ग में संयुक्त रूप से दूसरा स्थान हासिल किया। वेदिका गर्ल्स-10 में तीसरे और आद्या थिम्मैया गर्ल्स-12 में चौथे स्थान पर रहीं। वहीं, अर्शवंत श्रीवास्तव ने यूएस किड्स वर्ल्ड टीन चैंपियनशिप में संयुक्त रूप से चौथा स्थान हासिल किया। इंडिया सीरीज की खासियत खिलाड़ियों के लिए यूएस किड्स गोल्फ प्रायोरिटी स्टेटस हासिल करने का अवसर है। प्रदर्शन के आधार पर मिलने वाला यह दर्जा खिलाड़ियों को प्रमुख अंतरराष्ट्रीय जूनियर प्रतियोगिताओं में आमंत्रण और प्रवेश दिलाने में मदद करता है।

यूएस किड्स इंडिया एंड एशिया के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव ने कहा कि एशिया में इस कार्यक्रम का विस्तार तेजी से हुआ है और अकेले इस वर्ष 100 से अधिक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में एशियाई खिलाड़ियों को अधिक अंतरराष्ट्रीय अनुभव और प्रतिस्पर्धी अवसर देने के लिए एशियन टूर विकसित करने पर काम किया जा रहा है। कार्यक्रम

का विस्तार अब चीन, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान समेत 10 से अधिक एशियाई देशों तक हो चुका है। इसका दीर्घकालिक लक्ष्य भारत और एशिया के स्थानीय टूर्नामेंटों से खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय जूनियर गोल्फ प्रतियोगिताओं तक पहुंचने का व्यवस्थित मार्ग उपलब्ध कराना है।

दलीप ट्रॉफी फाइनल में ईस्ट जोन की खिताब पर मजबूत पकड़, 584 रन की बढ़त

चेन्नई। कप्तान ईशान किशन और शिखर मोहन के अर्धशतकों की बदौलत ईस्ट जोन ने दलीप ट्रॉफी फाइनल में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। बुधवार को चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक ईस्ट जोन ने दूसरी पारी में पांच विकेट पर 212 रन बनाकर साउथ जोन के खिलाफ कुल 584 रन की विशाल बढ़त हासिल कर ली। ईशान किशन ने मैच में कुल 350 रन बनाए। उन्होंने दूसरी पारी में 80 रन की पारी खेली और शतक से 20 रन दूर रह गए। इससे पहले तिलक वर्मा भी सुबह के सत्र में अपने शतक से महज एक रन से चूक गए और 99 रन पर आउट हुए। चौथे दिन सुबह ईस्ट जोन ने अपने बाकी चार विकेट के लिए 94 रन जोड़े। नाबाद अर्धशतक के साथ दिन की शुरुआत करने वाले तिलक वर्मा ने नई गेंद से मोहम्मद शमी के पहले ही ओवर में लगातार दो चौके लगाए। दूसरे छोर पर सीवी मिलिंद ने मुकेश कुमार के खिलाफ शानदार कवर ड्राइव के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने नई गेंद के खिलाफ तेजी से रन बनाए। साउथ जोन ने इसके बाद दोनों छोर से स्पिनरों को गेंदबाजी पर लगाया और यह रणनीति काम आई। मिलिंद का विकेट गिरने के बाद साउथ जोन को वापसी का मौका मिला। तिलक के स्ट्राइक बचाने के प्रयास में त्रिपुराना विजय रन आउट हो गए। इसके बाद मोहम्मद सिराज को मुकेश कुमार के सामने लाया गया और मुकेश ने उन्हें पगबाधा आउट कर दिया। अगले ओवर में तिलक

वर्मा 99 रन पर गेंदबाज को कैच देकर पवेलियन लौट गए और उनका शानदार शतक एक रन से छूट गया।

पहली पारी में 372 रन की बढ़त हासिल करने के बावजूद ईस्ट जोन ने साउथ जोन को फॉलोऑन नहीं दिया और दोबारा बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस फैसले से दर्शकों को वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी देखने का एक और मौका मिला, लेकिन वह सिर्फ आठ रन बनाकर आउट हो गए। त्रिपुराना विजय की गेंद पर आगे निकलकर खेलने के प्रयास में वह स्टंप हो गए। इससे पहले अभिमन्यु ईश्वरन मोहम्मद सिराज की गेंद पर पहली स्लिप में कैच दे बैठे। शुरुआती झटकों के बाद ईशान किशन और शिखर मोहन ने पारी को संभाला। टीम की बढ़त 400 रन के पार पहुंचने के बाद ईशान ने विजय की गेंद पर छक्का लगाया, जबकि मोहन ने श्रेयस गोपाल की गेंद पर सीधे मैदान के बीच से चौका जड़ा। दोनों ने सकारात्मक अंदाज में बल्लेबाजी जारी रखी। चाय के बाद ईशान ने आक्रामक रुख अपना लिया। अर्धशतक पूरा करने के बाद उन्होंने अगले ही ओवर में त्रिपुराना विजय के खिलाफ लगातार चार गेंदों पर 4, 6, 6, 4 रन बटोरे। ऐसा लग रहा था कि ईशान एक और शतक की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन श्रेयस गोपाल और एमडी निहीद ने रन गति पर अंकुश लगाया। इसके बाद बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में ईशान कैच दे बैठे और 80 रन पर पवेलियन लौट गए। ईशान के आउट होने के बाद शिखर मोहन को शेख रशीद ने पगबाधा आउट किया, जबकि सुदीप घरामी रन आउट होकर जल्दी पवेलियन लौट गए। इसके बाद कुमार कुशाग्र और एमडी कौनेन कुरैशी ने दिन का बाकी खेल संभाला और अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की। संक्षिप्त स्कोर: ईस्ट जोन 708 और 5 विकेट पर 212 रन (ईशान किशन 80, शिखर मोहन 52) बनाकर साउथ जोन 336 रन (तिलक वर्मा 99; मुकेश कुमार 3/62) से कुल 584 रन आगे।

यूएस ओपन: फ्रांसेस टियाफोए ने एलेक्स माइकलसन को हराया, सेमीफाइनल में पहुंचे

न्यूयॉर्क। फ्रांसेस टियाफोए ने शानदार जुझारूपन का परिचय देते हुए यूएस ओपन 2026 के पुरुष एकल सेमीफाइनल में जगह बना ली है। 11वीं वरीयता प्राप्त अमेरिकी खिलाड़ी ने मंगलवार को क्वार्टर फाइनल में एलेक्स माइकलसन को 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6 (10-6) से हराया। टियाफोए ने मुकाबले में पहले दो सेट गंवाने के बाद जोरदार वापसी की। वह निर्णायक पांचवें सेट में भी 0-3 से पीछे थे, लेकिन उन्होंने लगातार वापसी करते हुए चार घंटे 38 मिनट तक चले मुकाबले को अपने नाम कर लिया। मैच के बाद टियाफोए नेट के दूसरी तरफ पहुंचे, जहां 22 वर्षीय माइकलसन अपने पहले ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल के निराशाजनक अंत के बाद रो रहे थे। टियाफोए ने उन्हें गले लगाकर सांत्वना दी। टियाफोए ने मैच की शुरुआत को लेकर कहा, 'यह अच्छा नहीं था, इसे इसी तरह कहना चाहिए। यह बिल्कुल अच्छा नहीं था। पांच में से तीन सेट का प्रारूप एक वरदान है, क्योंकि आपके पास वापसी करने और चीजों को सही करने का समय होता है। मैंने निश्चित रूप से आखिरी समय तक इंतजार किया। टियाफोए इससे पहले 2022 और 2024 में भी यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे थे। अब सेमीफाइनल में उनका सामना गत चैंपियन कार्लोस अल्काराज और आठवीं वरीयता प्राप्त बेन शेल्टन के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। टियाफोए ने 2022 के सेमीफाइनल में अल्काराज के खिलाफ हार झेली थी, जबकि 2024 में उन्हें हमवतन टेलर फ्रिट्ज ने हराया था। इस बार टियाफोए की जीत ने अमेरिकी पुरुष खिलाड़ी के ग्रैंड स्लैम खिताब के लंबे इंतजार को खत्म करने की उम्मीदों को फिर मजबूत किया है। अमेरिका ने आखिरी बार 2003 में एंडी रॉडिक के जरिये पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था।

माइकलसन मुकाबले में मजबूत स्थिति में थे। वह टूर्नामेंट में एक भी सेट गंवाए बिना क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे और तीसरे सेट में 5-4 की बढ़त के साथ मैच जीतने के लिए सर्विस कर रहे थे। हालांकि, लगातार दो डबल फॉल्ट के बाद वह दबाव में आ गए और टियाफोए ने ब्रेक हासिल कर तीसरा सेट अपने नाम कर लिया। माइकलसन ने कहा, 'मुझे लगा कि पहले तीन सेट में मैं उस पर हावी था। वह फ्रांसेस की तरह नहीं खेल रहे थे। फिर 5-4 पर मैंने उन्हें वापसी का मौका दे दिया। इसके बाद वह आर्थर ऐश में अपने अंदाज में खेलने लगे। फिर मुकाबला पूरी तरह संघर्ष में बदल गया। पांचवें सेट में भी माइकलसन ने शुरुआत में टियाफोए की सर्विस तोड़कर 3-0 की बढ़त बना ली थी। टियाफोए ने गुस्से में एक समय अपना रैकेट कोर्ट पर पटक दिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने फिर वापसी की। मैच टाईब्रेक में टियाफोए ने लगातार तीन अंक जीतकर 7-4 की बढ़त बनाई और फिर 135 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ऐस लगाकर जीत की ओर कदम बढ़ाया। इस जीत के साथ टियाफोए इस सदी में आंद्रे अगासी के बाद तीन बार यूएस ओपन सेमीफाइनल में पहुंचने वाले दूसरे अमेरिकी पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। अगले विश्व रैंकिंग में वह तीन साल बाद पहली बार शीर्ष-10 में भी वापसी करेंगे। वहीं, 46वीं रैंकिंग वाले माइकलसन पांच सेट तक गए मुकाबलों में अपनी छठी हार के साथ अब तक एक भी जीत दर्ज नहीं कर सके हैं।

एक नजर

नेपाल में बाढ़ से अब तक 1,365 की मौत, 4,077 अब भी लापता

काठमांडू,एजेंसी। नेपाल के भोटेकोशी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक 1,365 लोगों की मौत हो चुकी है और 4,077 लोग अभी भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों से विस्थापित हुए 3,030 लोग विभिन्न जिलों में बनाए गए अस्थायी शिविरों में रह रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि सर्वाधिक शव चितवन में 363 बरामद हुए हैं। इसके बाद पूर्वी नवलपरासी में 226, पश्चिमी नवलपरासी में 222, नुवाकोट में 197, रसुवा में 174, गोरखा में 75, धादिङ में 70 और तनहुँ में 38 शव बरामद किए गए हैं। अधिकारियों ने अब तक 1,147 शवों को दफनाया है। शवों से डीएनए नमूने लेने और आवश्यक पहचान प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें सुरक्षित तरीके से दफनाया गया है। पीड़ितों की पहचान के प्रयासों के तहत फॉरेंसिक टीमों ने अब तक 2,698 डीएनए नमूने एकत्र किए हैं। इनमें 1,286 नमूने पीड़ितों के और 1,412 उनके परिजनों के हैं। वहीं, 1,310 अज्ञात शवों का विवरण नेपाल पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक किया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में खोज और बचाव अभियान लगातार जारी है। राहत वितरण, शवों की बरामदगी और अब भी लापता लोगों की तलाश के लिए कुल 7,975 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, 4,077 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि विस्थापित हुए 3,030 लोग विभिन्न जिलों में बनाए गए अस्थायी होल्डिंग सेंटरों में रह रहे हैं।

यूएई समेत आठ मुस्लिम देशों ने इजराइली बस्तियों पर ब्रिटेन के प्रतिबंधों का किया समर्थन

दोहा/अबू धाबी,एजेंसी। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) समेत आठ मुस्लिम-बहुल देशों ने वेस्ट बैंक में इजराइली बस्तियों के खिलाफ ब्रिटेन की ओर से घोषित प्रतिबंधों का समर्थन किया है। इन देशों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से ब्रिटेन के कदम का अनुसरण करते हुए अवैध बस्ती गतिविधियों में शामिल संगठनों और व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान किया है। कतर, तुर्किये, मिस्र, इंडोनेशिया, जॉर्डन, पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान जारी कर ब्रिटेन के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह कदम अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप इसी तरह की कार्रवाई करने और अवैध बस्ती गतिविधियों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए प्रेरित करेगा। बयान में गाजा युद्ध के बाद की स्थिति को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना को पूरी तरह और तत्काल लागू करने की भी अपील की गई। इन देशों ने पूर्वी यरुशलम को राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना का समर्थन दोहराया। इजराइल फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की इस मांग का विरोध करता है। वहीं, वेस्ट बैंक में इजराइली बस्तियों का मुद्दा लंबे समय से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद का प्रमुख विषय बना हुआ है।

इजराइली हिरासत केंद्र पहुंची रेड क्रॉस की टीम, फिलिस्तीनी कैदियों से नहीं हो सकी मुलाकात

तेल अवीव। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति (आईसीआरसी) की एक टीम ने बुधवार को इजराइल की एक सैन्य हिरासत सुविधा में सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। यह बैठक इजराइली जेलों में बंद फिलिस्तीनी सुरक्षा कैदियों और हिरासत में रखे गए लोगों तक रेड क्रॉस की पहुंच बहाल करने के प्रयासों का हिस्सा थी। इजराइल में आईसीआरसी के प्रमुख जूलियन लेरिसन के अनुसार, टीम ने अधिकारियों के साथ तकनीकी बैठक की और हिरासत सुविधा का दौरा भी किया। हालांकि, टीम को वहां रखे गए फिलिस्तीनी कैदियों से मिलने या उनसे सीधे संपर्क करने की अनुमति नहीं मिली। लेरिसन ने बातचीत को सकारात्मक बताते हुए इसे हिरासत में रखे लोगों के लिए उचित रेड क्रॉस यात्राएं दोबारा शुरू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि संगठन संबंधित अधिकारियों के साथ यात्राओं के प्रारूप और शर्तों पर बातचीत जारी रखेगा, ताकि इन मुलाकातों को फिर से शुरू किया जा सके। इजराइल ने 07 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व में हुए हमले के बाद फिलिस्तीनी सुरक्षा कैदियों से आईसीआरसी की नियमित मुलाकातें रोक दी थीं। इस बीच, इस वर्ष इजराइल के हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि सरकार इन यात्राओं पर रोक नहीं लगा सकती।

इजराइली हिरासत केंद्र पहुंची रेड क्रॉस की टीम, फिलिस्तीनी कैदियों से नहीं हो सकी मुलाकात

तेल अवीव। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति (आईसीआरसी) की एक टीम ने बुधवार को इजराइल की एक सैन्य हिरासत सुविधा में सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। यह बैठक इजराइली जेलों में बंद फिलिस्तीनी सुरक्षा कैदियों और हिरासत में रखे गए लोगों तक रेड क्रॉस की पहुंच बहाल करने के प्रयासों का हिस्सा थी। इजराइल में आईसीआरसी के प्रमुख जूलियन लेरिसन के अनुसार, टीम ने अधिकारियों के साथ तकनीकी बैठक की और हिरासत सुविधा का दौरा भी किया। हालांकि, टीम को वहां रखे गए फिलिस्तीनी कैदियों से मिलने या उनसे सीधे संपर्क करने की अनुमति नहीं मिली। लेरिसन ने बातचीत को सकारात्मक बताते हुए इसे हिरासत में रखे लोगों के लिए उचित रेड क्रॉस यात्राएं दोबारा शुरू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि संगठन संबंधित अधिकारियों के साथ यात्राओं के प्रारूप और शर्तों पर बातचीत जारी रखेगा, ताकि इन मुलाकातों को फिर से शुरू किया जा सके। इजराइल ने 07 अक्टूबर 202× को हमास के नेतृत्व में हुए हमले के बाद फिलिस्तीनी सुरक्षा कैदियों से आईसीआरसी की नियमित मुलाकातें रोक दी थीं। इस बीच, इस वर्ष इजराइल के हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि सरकार इन यात्राओं पर रोक नहीं लगा सकती।

सीरिया पहुंचे नेतन्याहू, बोले- ईरान की हार करीब, सीमा पर आतंकी सेना को नहीं जमने देंगे

दमिश्क। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि उनका देश ईरान को पराजित करने के बेहद करीब पहुंच गया है। सीरियाई क्षेत्र में स्थित माउंट हर्मोन के दौरे के दौरान नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल अपनी सीमा के पास किसी भी 'आतंकी सेना' को पैर जमाने की अनुमति नहीं देगा। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के नेतृत्व वाले क्षेत्रीय नेटवर्क के कमजोर पड़ने की प्रक्रिया अंततः पूरी होगी। उन्होंने ईरान की सरकार को 'आतंकी शासन' बताते हुए कहा कि उसे हराना इजरायल के सामने मुख्य कार्य है और उनका देश इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इजरायली प्रधानमंत्री ने सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में से एक बताया। उनका इशारा सीरिया के उस बफर जोन की ओर माना जा रहा है, जिस पर इजरायल ने बशर अल-असद शासन के पतन के बाद नियंत्रण स्थापित किया था। नेतन्याहू ने यह बयान इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज और उप सेनाध्यक्ष मेजर जनरल तामिर यादाई के साथ माउंट हर्मोन के दौरे के दौरान दिया। इजरायल और अमेरिका ने फरवरी के अंत में ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था। हालांकि अप्रैल में इजरायल और ईरान के बीच सीधी लड़ाई काफी हद तक थम गई थी।

बलोचिस्तान में पाकिस्तान के सैन्य वाहनों पर फायरिंग, हमले में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने का दावा

इस्लामाबाद,एजेंसी। पाकिस्तान के बलोचिस्तान के खारान और पंजगुर जिलों में पाकिस्तान की सेना के वाहनों को निशाना बनाया गया है। हथियारबंद लोगों के इस हमले में बड़ा विस्मयकारी दावा किया गया है। इस दावे के अनुसार, हमले में 1,000 सैन्यकर्मी मारे गए या घायल हुए। इस दावे पर पाकिस्तान सरकार या संघीय सेना ने अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है। अभी तक किसी संगठन ने भी इस तरह के हमले की जिम्मेदारी ली है। द बलोचिस्तान पोस्ट की 08 सितंबर की शाम जारी रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय सूत्रों ने बताया कि हथियारबंद लोगों ने शाम को खारान शहर के पास पाकिस्तान की सेना की गाड़ियों को निशाना बनाया। सूत्रों का कहना है कि हमले के दौरान सेना की कम से कम तीन गाड़ियों पर सीधी फायरिंग हुई। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, हमले में लगभग 1,000 सैन्यकर्मी मारे गए या घायल हुए। अधिकारियों की ओर से घटना, हताहतों या हमले के बारे में तुरंत कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

इस बीच, पंजगुर जिले के प्रोम इलाके में बंदूकधारियों ने पाकिस्तान की सेना के लिए राशन ले जा रही एक गाड़ी में आग लगा दी। सूत्रों के अनुसार, इस दौरान हथियारबंद लोगों ने एक और गाड़ी पर भी कब्जा कर लिया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, हथियारबंद लोगों ने पंजगुर के चिडगी इलाके में एक रिहायशी इलाके में आग लगाने की घटना में पाकिस्तान की सेना द्वारा लगाए गए सर्विलांस कैमरों को नष्ट कर दिया। इन हमलों की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है। हालांकि बलोच आजादी समर्थक संगठन ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी लेते रहे हैं। द बलोचिस्तान पोस्ट की एक पुरानी रिपोर्ट के अनुसार, बलोच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के मीडिया विंग के पूर्व में जारी आंकड़ों के मुताबिक, बीएलए ने पाकिस्तान के सुरक्षा बलों, सैन्य ठिकानों और वाहनों को निशाना बनाते हुए 500 से अधिक हमले किए। इनमें 1,000 से अधिक सैनिकों के मारे जाने या गंभीर रूप से घायल हुए। वर्ष 2026 में मस्तुंग, क्वेटा, कलात, और बोलन में व्यापक टकराव देखा गया है। बीएलए के फतह स्क्वायड और अन्य विशेष शाखाओं ने संघीय सरकार के सैन्य काफिलों को निशाना बनाकर कई घातक हमले किए हैं। इन हमलों में जियारत क्रॉस और सूराब क्षेत्रों में कई पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया गया। पाकिस्तान सरकार और सेना (आईएसपीआर) आमतौर पर बलोच विद्रोही गुटों के दावों को खारिज करती है या हताहतों की बहुत कम संख्या बताती है। पाकिस्तान के सुरक्षा बल भी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चला रहे हैं। इन अभियानों में सैकड़ों बलोच लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया गया है। संघर्ष क्षेत्र होने और मीडिया पर कड़े प्रतिबंधों के कारण, दोनों पक्षों (बीएलए और पाकिस्तान की सेना) के हताहतों के इन बड़े आंकड़ों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना बेहद कठिन है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने बलोचिस्तान निवासी इमरान अली को जबरन गायब किए जाने और उसकी न्यायेतर हत्या को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए पाकिस्तान से मामले की त्वरित एवं निष्पक्ष जांच करने का आग्रह किया है। बताया गया है कि पिछले साल 27 अगस्त को पाकिस्तान के आतंकवाद रोधी विभाग के करीब 20 अधिकारियों ने अली को उसके अपार्टमेंट से कथित तौर पर अगवा कर लिया था और वे उसे किसी अज्ञात स्थान पर ले गए थे। अली के परिवार को एक साल तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई कि वह कहां है और उसके साथ क्या हुआ।

अमेरिका का कनाडा के डेयरी प्रोडक्ट और शराब पर प्रतिबंध, कनाडा के जवाबी टैरिफ के बाद फैसला, 29 सितंबर से होगा लागू

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाले डेयरी प्रोडक्ट, शराब और मोटरसाइकिलों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यह प्रतिबंध 29 सितंबर से लागू होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह फैसला अमेरिकी सामान पर 50 फीसद तक जवाबी टैरिफ लगाने के बाद लिया है। इस आदेश के तहत कनाडा से आने वाली शराब, वाइन और अल्कोहल-फ्री बीयर पर रोक लगेगी। इसके अलावा दूध से बने कुछ उत्पाद भी अमेरिका नहीं आ सकेंगे। एक्सिओस की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि प्रतिबंध को सीमित रखा गया है, ताकि अमेरिकी नागरिकों के लिए सामान की कीमतें अचानक न बढ़ें। राष्ट्रपति ट्रंप का यह कदम उन देशों के बीच आर्थिक दरार को और गहरा करने वाला है, जिन्होंने दशकों से व्यापार को आपस में जोड़ा है, जिससे सीमा के दोनों ओर व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए व्यवधान का खतरा पैदा हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 1930 के टैरिफ एक्ट की धारा 338 के तहत ताजा प्रतिबंध लगाए हैं। यह एक्ट राष्ट्रपति को ऐसे देशों से आयात रोकने की अनुमति देता है जो अमेरिकी व्यापार के खिलाफ भेदभाव बनाए रखते हैं या बढ़ाते हैं। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को कहा कि 15 सितंबर से दर्जनों अन्य कनाडाई उत्पादों (स्टील और एल्यूमीनियम के सामान, फर्नीचर और कागज) पर मौजूदा 50 फीसद टैरिफ का दायरा भी बढ़ाएगा।

पिछले महीने अमेरिका-कनाडा के बीच बातचीत टूटने के बाद से व्यापारिक तनाव तेजी से बढ़ा है। अमेरिका ने कनाडा के लगभग 20 अरब डॉलर के सामान पर 50 फीसद टैरिफ लगाया। जवाब में कनाडा ने भी अमेरिका के इतने ही मूल्य के सामान पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया। इसके बाद से ट्रंप ने अगले साल से कनाडा की गाड़ियों पर और ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दी है। उन्होंने सोमवार को कनाडा की विमान बनाने वाली कंपनी बॉम्बार्डियर को अमेरिका में अपने जेट बेचने से रोकने की धमकी भी दी। एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि इस पर अभी विचार किया जा रहा है। ट्रंप ने मंगलवार को 'ट्रुथ सोशल' पर कहा कि वह अधिकारियों को निर्देश देंगे कि वे कनाडा में बने उत्पादों को अमेरिकी सरकार के कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर रखें, 'जब तक कनाडा अमेरिकी किसानों और कंपनियों के लिए पूरी तरह से निष्पक्ष और बराबरी का व्यवहार बहाल नहीं करता।'

नेपाल में बाढ़ के चलते उत्तरी सीमा से आपूर्ति प्रभावित, सीमा शुल्क राजस्व पर पड़ा असर

काठमांडू। रसुवा में आई विनाशकारी बाढ़ और कृष्णभीर में सड़क धंसने से उत्तरी सीमा से होने वाली आपूर्ति बाधित हुई है, जिसका सीमा शुल्क राजस्व पर भी बड़ा असर पड़ा है। वित्त सचिव डॉ. घनश्याम उपाध्याय ने बताया कि रसुवागढ़ी सीमा नाके पर बाढ़ के कारण चीन से होने वाली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई थी। इसका सीधा असर सीमा शुल्क राजस्व में भी दिखाई दिया।

प्रतिनिधि सभा की वित्त समिति की बैठक में उपाध्याय ने कहा कि रसुवागढ़ी के विकल्प के तौर पर आयात को सुचारु करने के लिए सरकार ने कोराला सीमा नाके पर अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की थी। लेकिन कृष्णभीर में सड़क धंसने के बाद स्थिति और गंभीर हो गई तथा आपूर्ति मार्ग भी बाधित हो गया। उपाध्याय के अनुसार बाढ़ में बेत्रावती-रसुवागढ़ी सड़क का 55 किलोमीटर हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो गया है। वहीं गल्छी-देवीघाट सड़क के चार किलोमीटर हिस्से की पक्की सड़क को आंशिक नुकसान पहुंचा है। इसी तरह 10 किलोमीटर लंबी देवीघाट-त्रिशूली-बेत्रावती सड़क को भी आंशिक क्षति हुई है। उपाध्याय ने बताया कि चार जिलों में 33 मोटर चलने योग्य पुल पूरी तरह नष्ट हो गए, जबकि चार अन्य पुलों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 68 झूला पुल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं।उन्होंने बताया कि क्षतिग्रस्त मोटर चलने योग्य पुलों की कुल लंबाई करीब 3,000 मीटर है। वित्त सचिव के अनुसार वित्तीय क्षेत्र में 12 बैंकों की 17 शाखाएं पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई हैं। आपदा से करीब 4,800 व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी प्रभावित हुए हैं। परिवहन के अलावा अन्य क्षेत्रों पर भी आपदा का व्यापक असर पड़ा है। शिक्षा क्षेत्र को भी बड़ा नुकसान हुआ है। 18 स्कूलों के 56 भवन पूरी तरह नष्ट हो गए, जिनमें कुल 308 कक्षाएं थीं। कुल 7,570 निजी भवन पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। 48 सरकारी भवनों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 35 पूरी तरह नष्ट हो गए। विस्तृत आकलन के अनुसार बाढ़ से 1,259 होटल और रेस्तरां, 1,212 थोक एवं खुदरा कारोबार तथा बिजली, गैस और पानी से संबंधित 345 परियोजनाओं को गंभीर नुकसान पहुंचा है। इसी तरह 263 विनिर्माण उद्योग और सेवा क्षेत्र से जुड़ी 227 गतिविधियां भी गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं।कृषि क्षेत्र में भी नुकसान हुआ है। बाढ़ से 1,806 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि प्रभावित हुई है।

नेपाल में राहत-बचाव अभियान के लिए भारत की मदद जारी, 130 टन से अधिक राहत सामग्री पहुंचाई

काठमांडू,एजेंसी। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद जारी राहत और बचाव अभियान में भारत लगातार मानवीय सहायता उपलब्ध करा रहा है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार, भारतीय वायुसेना का आठवां विमान बुधवार को राहत सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। भारत ने 26 अगस्त 2026 से अब तक आठ विशेष उड़ानों के जरिए नेपाल को 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। इसके अलावा, बचाव, राहत और फॉरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए भारत से 54 विशेषज्ञ कर्मियों को नेपाल भेजा गया है। भारत की ओर से टेंट, कंबल, हाइजीन किट, सोलर लैंप और दवाओं के अलावा विशेष उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें टनल और कीचड़ में बचाव के उपकरण, मड रेस्क्यू सूट, गैस डिटेक्टर, ब्रीदिंग अपरेटस, इन्फ्लेटेबल वॉकवे, डीएनए किट और डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए जरूरी उपकरण व रिएजेंट शामिल हैं। इसके साथ ही पोर्टेबल जनरेटर, लाइटिंग टावर और पानी निकालने वाले पंप भी भेजे गए हैं।

भारतीय विशेषज्ञों की विशेष टनल रेस्क्यू टीम ने नेपाली सेना के साथ समन्वय में चिलिमे और लांगटांग में बचाव अभियान शुरू किया था। फिलहाल खोज और बचाव अभियान का मुख्य फोकस चिलिमे पर है। यहां कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, पहुंच की समस्या और सुरंग के ढलान के कारण बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। भारतीय टीम मैनुअल प्रयासों और नई तकनीकों के जरिए लगातार काम कर रही है। सुरंग तक भारी मशीनरी, जिसमें एक्स्काभेटर भी शामिल है, पहुंचाने के लिए एक अस्थायी ट्रैक तैयार किया जा रहा है। भारतीय दूतावास के मुताबिक, इस ट्रैक के निर्माण में उत्साहजनक प्रगति हुई है और इसके अगले 2-3 दिनों में पूरा होने की उम्मीद है। वहीं, भारतीय फॉरेंसिक टीम काठमांडू की दो प्रयोगशालाओं में नेपाली अधिकारियों के विशेषज्ञों के साथ मिलकर डीएनए नमूनों की जांच और विश्लेषण कर रही है। भारत की ओर से उपलब्ध कराए जा रहे फॉरेंसिक उपकरण, डीएनए किट और रिएजेंट इस प्रक्रिया में मदद करेंगे। भारतीय दूतावास ने कहा है कि भारत नेपाल की जनता और सरकार को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है और देश में बचाव, राहत एवं पुनर्वास के प्रयासों में अपना सहयोग जारी रखेगा।

भारत के चीनी निर्यात प्रतिबंध से बढ़ी कीमतों पर नेपाल की संसदीय समिति की चिंता

काठमांडू,एजेंसी। नेपाल के उद्योग एवं वाणिज्य तथा श्रम एवं उपभोक्ता हित संसदीय समिति के अध्यक्ष रहबर अंसारी ने भारत द्वारा चीनी के निर्यात पर रोक लगाए जाने के बाद नेपाल में उत्पन्न स्थिति, बाजार में बढ़ती कीमतों और उपभोक्ताओं के हितों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अंसारी ने संसदीय समिति की बैठक के दौरान यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ ही महीनों में चीनी की कीमतों में हुई तेज बढ़ोतरी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जबकि इससे पहले आश्वासन दिया गया था कि बाजार में पर्याप्त चीनी का स्टॉक मौजूद है और भारत द्वारा निर्यात रोकने के बावजूद कीमतों में वृद्धि नहीं होगी। समिति ने यह भी सवाल उठाया कि चीनी की कीमत बढ़कर 130 रुपये प्रति किलोग्राम तक कैसे पहुंच गई।

अंसारी ने कहा कि पहले चीनी की कीमत 85 रुपये प्रति किलोग्राम रहने की उम्मीद थी और वैट जोड़ने के बाद यह करीब 96 रुपये पड़ती थी। लेकिन अब बाजार में चीनी 105 से 130 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक रही है। उन्होंने पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद कीमतों में वृद्धि के कारणों की जांच करने की जरूरत पर जोर दिया। समिति के अध्यक्ष ने कहा कि मौजूदा कमी और कीमतों में बढ़ोतरी का एक कारण अन्य देशों से समय पर चीनी का आयात नहीं किया जाना भी है। उन्होंने मंत्रालय से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने, कार्टेलिंग और कालाबाजारी को नियंत्रित करने के लिए संसद में आवश्यक विधेयक और कानून जल्द पेश करने का आग्रह किया। अंसारी ने कहा कि बाजार की निगरानी व्यवस्था को अधिक व्यावहारिक और तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए। साथ ही महंगे सॉफ्टवेयर की खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान और ईंधन आपूर्ति की समस्याओं के कारण बढ़ी परिवहन लागत जैसी व्यावहारिक समस्याओं को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता बताई।

केपी शर्मा ओली ने कहा- नेपाल में जेन जी हिंसा थी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद पर बड़ा हमला

काठमांडू। सीपीएन-यूएमएल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने 9 सितंबर, 2025 को 'भयानक तबाही का दिन' बताते हुए कहा है कि जेन-जी प्रदर्शनों के बाद हुई हिंसा राज्य, लोकतंत्र और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद पर बड़ा हमला थी।

घटनाओं की पहली बरसी के मौके पर बुधवार को जारी वीडियो संदेश में ओली ने कहा कि जेन-जी आंदोलन 8 सितंबर को शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ था, लेकिन बाद में आपराधिक समूह इसमें घुस गए और उनके अनुसार, जानबूझकर प्रदर्शन को हिंसक बना दिया। ओली ने कहा कि युवा सुशासन और सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंधों जैसे मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरे थे। उन्होंने कहा कि संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि आपराधिक समूहों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन में घुसकर हिंसा भड़काई। ओली के अनुसार, युवा प्रदर्शनकारियों को जानबूझकर घेरकर संसद भवन की ओर ले जाया गया, जहां स्थिति बिगड़ गई और गोलीबारी में लोगों की मौत हुई। ओली ने आंदोलन के दौरान मारे गए युवाओं और ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों को याद करते हुए उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने उपचार करा रहे घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की। हालांकि, ओली ने कहा कि 9 सितंबर की घटनाएं पिछले दिन हुई मौतों से पैदा हुए आक्रोश से कहीं आगे निकल गई थीं। उन्होंने राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास, सिंहदरबार, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, राजनीतिक दलों के कार्यालयों तथा सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर हुए हमलों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर हुई तोड़फोड़, लूटपाट, आगजनी और जनहानि को केवल पिछले दिन हुई मौतों पर भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं माना जा सकता।

ओली ने 9 सितंबर की घटनाओं को एक कथित 'खतरनाक साजिश' का परिणाम बताया। उनके मुताबिक, इसका उद्देश्य राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था के नेपाल के प्रगतिशील रास्ते को पलटना और देश को निरंकुशता तथा अराजकता की ओर धकेलना था। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि तबाही के लिए जिम्मेदार लोगों को अब तक जवाबदेह क्यों नहीं ठहराया गया। ओली ने पूछा, '9 सितंबर की तबाही के आरोपियों को छूट क्यों दी जा रही है? रिपोर्टों को गोपनीय क्यों रखा जा रहा है?' ओली ने कहा कि युवा प्रदर्शनकारियों की चिंताएं और उनकी मंशा वास्तविक थीं, लेकिन जेन-जी आंदोलन के नाम पर हुई हिंसा का फायदा अन्य ताकतों ने उठाया। उन्होंने कहा कि युवाओं में असंतोष अभी भी व्यापक है और पिछले साल की घटनाओं को दोबारा नहीं होने देना चाहिए। ओली ने लोकतांत्रिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों के खिलाफ नफरत तथा बदले की भावना फैलाने के प्रयासों की भी आलोचना की। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी गतिविधियां देश को और अधिक पीछे धकेल सकती हैं।

एक नजर

धर्मांतरण के दबाव का विरोध करने पर परिवार से मारपीट, पांच गिरफ्तार

कानपुर,एजेंसी। गुजैनी थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगलवार को धर्मांतरण के कथित दबाव का विरोध करने और घर में बनाई गई मजार हटाने की बात कहने पर ई-रिक्शा चालक सोनू जाटव और उसके परिवार के साथ मारपीट की गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। बुधवार को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रामगोपाल चौराहा के पास वरुण विहार की कच्ची बस्ती में हुई घटना के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था। भाजपा, हिंदू जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए थाने का घेराव किया था। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मारपीट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए बस्ती निवासी शीबू, मो. समीम, आमिर खान उर्फ पूतन, अरमान और अरसलान को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने के आरोपों को भी शामिल किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपों की पड़ताल के बाद मुकदमे में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धाराएं बढ़ाई गई हैं। जांच के दौरान बस्ती में जमीन पर कब्जे और झोपड़ियां बनाकर किराए पर देने के आरोप भी सामने आए हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि करीब सात-आठ वर्ष पहले हाईटेंशन लाइन के नीचे नगर निगम की ग्रीन बेल्ट में झोपड़ियां बनाई गई थीं। आरोप है कि इन्हें किराए पर देने के बाद कुछ लोगों पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया गया। विरोध करने वालों से झोपड़ियां खाली कराने का भी आरोप है। पुलिस के मुताबिक बाद में आरोपी के परिचित और रिश्तेदारों के परिवार वहां रहने लगे। वर्तमान में करीब 25 परिवारों के वहां रहने की जानकारी मिली है। इन तथ्यों की जांच के साथ स्थानीय खुफिया इकाई भी बस्ती में रहने वाले लोगों और उनके आपसी संबंधों की जानकारी जुटा रही है। वहीं, मामले में अन्य आरोपितों की तलाश में दबिश दी जा रही है। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि बस्ती में दोबारा विवाद की स्थिति न बने, इसके लिए पुलिस बल तैनात किया गया है और लगातार निगरानी की जा रही है। धर्मांतरण के दबाव, जमीन पर कब्जे और मारपीट से संबंधित आरोपों की जांच साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है।

बीआरएस ने राज्यपाल से की कांग्रेस सरकार के खिलाफ शिकायत, निष्पक्ष जांच की मांग

हैदराबाद। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने तेलंगाना में कांग्रेस सरकार पर पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ कथित दुर्व्यवहार और अत्याचार का आरोप लगाते हुए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से हस्तक्षेप की मांग की है। पार्टी ने बीआरएस विधायकों और महिला विधायकों पर हमले, उन्हें विधानसभा में प्रवेश से रोकने तथा पार्टी प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के आवास पर कथित हमले का मुद्दा उठाया। राज्यपाल ने बीआरएस प्रतिनिधिमंडल को उनके द्वारा उठाए गए मामलों की जांच कराने का आश्वासन दिया। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव के नेतृत्व में पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को लोक भवन में राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि होने के बावजूद बीआरएस विधायकों को सड़क पर रोका गया, विधानसभा परिसर में प्रवेश से रोका गया और उनके साथ मारपीट की गई।

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में केटी रामा राव ने कहा कि पार्टी ने विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और बीआरएस सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत राज्यपाल से की है। उन्होंने विशेष रूप से महिला विधायकों के साथ कथित मारपीट का मुद्दा उठाया। उनके अनुसार, इन घटनाओं से संबंधित तस्वीरें और अन्य साक्ष्य भी राज्यपाल को सौंपे गए हैं। रामा राव ने दावा किया कि उपलब्ध तस्वीरों में वी. सुनीता लक्ष्मा रेड्डी की साड़ी खींचने और पी. सबिता इंद्रा रेड्डी को बालों से घसीटने जैसी घटनाएं दिखाई देती हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच की मांग की है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष गड्डम प्रसाद कुमार से जुड़े विवाद का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ कांग्रेस अध्यक्ष के मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है और विधान परिषद सदस्यों के नाम पर ऐसी टिप्पणियां जोड़ी जा रही हैं, जो उनके अनुसार उन्होंने की ही नहीं थीं। रामा राव ने कहा कि बीआरएस के मन में विधानसभा अध्यक्ष के प्रति पूरा सम्मान है। हालांकि, उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह राजनीतिक स्वार्थ के लिए बार-बार अध्यक्ष की दलित पहचान का इस्तेमाल कर रही है।

आम आदमी पार्टी 27 सितंबर से विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत करेगी : संजय सिंह

लखनऊ,एजेंसी। आम आदमी पार्टी (आआपा) के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में बुधवार को राजधानी लखनऊ में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, जनहित के मुद्दों को आक्रामक ढंग से उठाने और आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर व्यापक चर्चा की गई। बैठक के बाद सांसद संजय सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस कर पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि पार्टी आगामी दिनों में तीन बड़े प्रदेशव्यापी कार्यक्रम करेगी। उन्होंने बताया कि सितंबर के अंतिम सप्ताह से आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलनों की शुरुआत करने जा रही है।

सांसद संजय सिंह ने बताया कि पार्टी के पहले बड़े अभियान के तहत 27 सितंबर को शहीद-ए-आज़म भगत सिंह की जयंती के अवसर पर प्रदेश के सभी ज़िलों में भव्य कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस दिन सभी ज़िला मुख्यालयों पर विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा और साथ ही बड़े पैमाने पर ब्लड डोनेशन (रक्तदान) शिविर लगाए जाएंगे, ताकि युवाओं को भगत सिंह जी के विचारों से जोड़ने के साथ-साथ समाज सेवा का संदेश दिया जा सके। उन्होंने बताया कि अक्टूबर माह से आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में एक विशाल जन-यात्रा निकालेगी। यह यात्रा बेरोज़गारी, भाजपा की नफ़रत की राजनीति, प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी, कमरतोड़ महंगाई और सामाजिक अन्याय के ख़िलाफ़ होगी। संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार को विकास के मुद्दे के मामले में घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़कों के टूटने, धंसने के मामले में कमीशन कमाने का खेल चल रहा है। 06 साल पहले मैंने जल जीवन मिशन में महाघोटाले का खुलासा किया था, आज उसी का नतीजा है कि बरेली में साढ़े तीन करोड़ की लागत से बनी पानी की टंकी बह गई। भाजपा ने न स्कूल छोड़ा, न अस्पताल, न सड़क, न बिजली, न पानी और प्रभु श्री राम का मंदिर, राम पथ और अयोध्या के श्मशान तक के रास्ते में भी भ्रष्टाचार कर डाला। प्रदेश में बेरोज़गारी और युवाओं का दमन किया जा रहा है। सांसद संजय सिंह ने कहा कि प्रयागराज में डीएलएड प्रशिक्षित युवा भीषण आंदोलन कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा में 02 लाख से अधिक पद खाली हैं, लेकिन सरकार भर्ती करने के बजाय स्कूल बंद कर रही है क्योंकि भाजपा का असली नारा है 'अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया'। संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की कितनी और कैसी हिस्सेदारी होगी, इस पर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय नेतृत्व के साथ विस्तार से चर्चा की जाएगी।

गणेशोत्सवः चेन्नई में गणेश प्रतिमाओं की ऊंचाई 10 फीट तक सीमित, स्थापना से विसर्जन तक पुलिस ने तय किए कड़े नियम

चेन्नई,एजेंसी। गणेशोत्सव से पहले चेन्नई पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर गणेश प्रतिमाओं की स्थापना को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने प्रतिमाओं की अधिकतम ऊंचाई आधार समेत 10 फीट तक सीमित कर दी है। प्रतिमा स्थापित करने से पहले भूमि मालिक की सहमति के साथ संबंधित स्थानीय निकाय, राजमार्ग विभाग अथवा अन्य सरकारी विभागों से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा अग्निशमन विभाग और बिजली बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करना भी जरूरी होगा। देशभर में 14 सितंबर से गणेशोत्सव मनाए जाने के मद्देनजर चेन्नई महानगर पुलिस ने कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में वेपेरी स्थित पुलिस आयुक्तालय में चेन्नई महानगर पुलिस आयुक्त अमलराज की अध्यक्षता में विभिन्न हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना, पूजा, जुलूस और समुद्र में विसर्जन को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर गणेश प्रतिमा स्थापित करने के लिए संबंधित पुलिस थाने में निर्धारित आवेदन देना होगा। आवेदन में निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों का पालन करने का लिखित आश्वासन देने के बाद ही पुलिस से अनुमति प्राप्त की जा सकेगी।

प्रतिमा स्थापना के लिए केवल पुलिस की अनुमति पर्याप्त नहीं होगी। आयोजकों को भूमि मालिक की सहमति लेने के साथ स्थानीय निकाय, राजमार्ग विभाग अथवा अन्य संबंधित सरकारी विभागों से आवश्यक अनुमति भी प्राप्त करनी होगी। अग्निशमन विभाग और बिजली बोर्ड से एनओसी लेना भी अनिवार्य किया गया है। पुलिस ने गणेश प्रतिमाओं के निर्माण में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) और जहरीले रसायनों का इस्तेमाल कर प्रतिमाएं बनाने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस ने कहा कि प्रतिमा स्थापना के दौरान पर्यावरणीय मानकों का ध्यान रखा जाना चाहिए और ऐसी सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, जिससे विसर्जन के बाद जलस्रोतों या समुद्री पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। पुलिस ने आयोजकों को अन्य पूजा स्थलों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के समीप गणेश प्रतिमा स्थापित करने से बचने का निर्देश दिया है।

15 साल बाद अंतरराष्ट्रीय मंच पर बंगाल, राष्ट्रमंडल सम्मेलन में प्रवासी बंगालियों से निवेश की अपील करेंगे विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष रथींद्र बोस 11 सितंबर को दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होंगे। वह केपटाउन में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल देशों के विधानसभा अध्यक्षों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। करीब 15 साल बाद पश्चिम बंगाल से इस स्तर के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष के शामिल होने की बात कही जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में भारत से करीब 70 से 80 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल सम्मेलन में हिस्सा लेगा। सम्मेलन में 56 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें भारत के संसदीय अनुभव, संसदीय परंपराओं के साथ आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और लोकतांत्रिक मूल्यों समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। दक्षिण अफ्रीका के बाद रथींद्र बोस अमेरिका और ब्रिटेन का भी दौरा करेंगे। इन दौरों के दौरान वह प्रवासी बंगालियों से पश्चिम बंगाल में निवेश करने की अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका यह आह्वान केवल विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर नहीं, बल्कि राज्य के एक नागरिक के रूप में भी होगा। बोस ने बुधवार को विधानसभा में मीडिया से बातचीत में कहा कि वह लोगों से पश्चिम बंगाल आने और राज्य को देखने की अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि बंगाल के विकास के लिए केवल भारी उद्योग या कारखानों में ही नहीं, बल्कि कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में निवेश करने वालों का भी खुले मन से स्वागत किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि वह राज्य की ओर से विदेश जा रहे हैं और प्रवासी बंगालियों से नए बंगाल में आने का आग्रह करेंगे। उनके मुताबिक उद्योग, साहित्य, संस्कृति और खेल समेत विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और सहयोग के लिए लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने पश्चिम बंगाल की कानून-व्यवस्था और शिक्षण संस्थानों से जुड़े हालिया विवादों पर भी प्रतिक्रिया दी। जलपाईगुड़ी जिला स्कूल में प्रधान शिक्षक के साथ कथित मारपीट की घटना पर भी उन्होंने चिंता जताई। विपक्ष की ओर से नई सरकार की लगातार आलोचना पर बोस ने फिलहाल ज्यादा ध्यान नहीं देने की बात कही। उन्होंने कहा, 'इस सरकार का अभी केवल पांच प्रतिशत समय बीता है। अभी से 'त्राहि मधुसूदन' का शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। अभी 95 प्रतिशत समय बाकी है।'

कांग्रेस का विभाजनकारी षड्यंत्र बेनकाब करें कार्यकर्ता : नितिन नवीन

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2027 में भाजपा की जीत का दिलाया संकल्प, धामी सरकार के कामकाज की सराहना

हल्द्वानी,एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को कांग्रेस और राहुल गांधी पर 'विभाजनकारी राजनीति' करने का आरोप लगाते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से विपक्ष की कथित तुष्टीकरण और जातिवाद की राजनीति को जनता के सामने बेनकाब करने का आह्वान किया। हल्द्वानी में भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के दूसरे सत्र को संबोधित करते हुए नवीन ने कहा कि उत्तराखंड भाजपा के लिए केवल एक राजनीतिक राज्य नहीं, बल्कि उसकी वैचारिक और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता की भूमि है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के साथ ही 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में मजबूती से जुटने का आह्वान किया। भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी ने हल्द्वानी की धरती से 'राजनीतिक षड्यंत्र' के तहत समाज को बांटने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कथित विभाजनकारी राजनीति का राजनीतिक और वैचारिक स्तर पर जवाब दिया जाना चाहिए।

नवीन ने कांग्रेस पर दलितों के साथ कथित दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए डॉ.भीमराव आंबेडकर, बाबू जगजीवन राम और सीताराम केसरी का उल्लेख किया। उन्होंने राजस्थान, कर्नाटक और केरल में दलित नेताओं एवं जनप्रतिनिधियों से जुड़े कथित मामलों का भी जिक्र किया और कांग्रेस पर 'वोट बैंक की राजनीति' के लिए दलित हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के दौर का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय वाल्मीकि समाज के लोगों को उच्च शिक्षा हासिल करने के बावजूद सफाई कर्मचारी के रूप में काम करने को मजबूर किया जाता था। नबीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉ. आंबेडकर से जुड़े 'पंचतीर्थ' विकसित कर उनके सम्मान को आगे बढ़ाया है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड का निर्माण किया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य को विकसित करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और शहीदों के आश्रितों के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करने जैसे कदम भाजपा की विचारधारा के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा की जीत केवल सरकार बनाने की जीत नहीं होगी, बल्कि यह पार्टी की विचारधारा की जीत भी होगी। नबीन ने कहा कि 'राष्ट्र प्रथम,पार्टी द्वितीय और स्वयं अंतिम' भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में स्टार्टअप, खेल और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिला है। उन्होंने दावा किया कि करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर लाया गया और 'लखपति दीदी' जैसी योजनाओं से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया गया।

भाजपा ने उत्तराखंड में हैट्रिक के साथ दो-तिहाई बहुमत का रखा लक्ष्य, शक्ति केंद्र आधारित रणनीति पर जोर

हल्द्वानी,एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने के साथ दो-तिहाई बहुमत हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। पार्टी केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों के विकास कार्यों तथा जनकल्याणकारी योजनाओं को आधार बनाकर जनता का विश्वास जीतने की रणनीति पर काम करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को प्रदेश पदाधिकारी एवं विस्तारित कार्यसमिति की बैठक में कार्यकर्ताओं से विकास और जनकल्याण के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता घर-घर संपर्क अभियान चलाकर भाजपा के पक्ष में बने जनसमर्थन को मतों में बदलने की रणनीति पर काम करें।

नवीन ने कार्यकर्ताओं से विपक्ष की कथित नकारात्मक राजनीति का राजनीतिक और लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देने की अपील करते हुए कहा कि चुनावी सफलता के लिए संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय और मजबूत करना होगा। उन्होंने कांग्रेस पर समाज को विभाजित करने की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को ऐसी राजनीति का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देना चाहिए। नबीन ने कहा कि चुनाव में भाजपा से मुकाबला नहीं कर पाने वाले लोग अब 'छद्म और षड्यंत्रकारी राजनीति' का सहारा ले रहे हैं और कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर इसका पर्दाफाश करना होगा। भाजपा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के कामकाज की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जनता का विश्वास भाजपा के पक्ष में है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से इस समर्थन को चुनावी सफलता में बदलने के लिए पूरी ताकत से जुटने का आह्वान किया। बैठक में पार्टी की चुनावी रणनीति में बदलाव का भी निर्णय लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि इस बार भाजपा मंडल के बजाय शक्ति केंद्र आधारित रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। मोर्चों की भूमिका बढ़ाते हुए उन्हें मंडल और शक्ति केंद्र स्तर पर संगठन को सक्रिय करने की जिम्मेदारी दी जाएगी।नवीन ने 'वंदे मातरम' को राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक बताते हुए विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दों को प्रमुखता से जनता के बीच रखना चाहिए।

नकारात्मकता का पर्दाफाश कर विकास के मुद्दे पर जनविश्वास हासिल करेगी भाजपाभाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अनुसार,पार्टी के तीन बार पदाधिकारी रह चुके और वर्तमान में किसी संगठनात्मक पद पर नहीं रहने वाले वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भी चुनावी रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की 'ऐतिहासिक हैट्रिक' और दो-तिहाई बहुमत हासिल करने के लक्ष्य के अनुरूप संगठनात्मक तैयारियां की जाएंगी। महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर-घर जाकर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां बताने तथा रोजगार, विकास, महिला, किसान और जनकल्याण के मुद्दों पर जनता का विश्वास हासिल करने का आह्वान किया।

कहा कि विपक्ष की जातिवाद, क्षेत्रवाद और भ्रम की नकारात्मक राजनीति का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दिया जाएगा। भाजपा सकारात्मक राजनीति के साथ राज्य के चुनावी इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल करेगी। तीरथ बोले- बूथ-बूथ जाकर जनआशीर्वाद से भाजपा को जिताने का समयभाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश कार्यसमिति को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव में बूथ स्तर तक सक्रिय होकर भाजपा की जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड का निर्माण किया और प्रधानमंत्री मोदी राज्य को संवारने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी एक अभिभावक की तरह उत्तराखंड के विकास, जनता के कल्याण और प्रदेश की समस्याओं की चिंता करते हैं। प्रदेश में संकट की किसी भी घड़ी में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री का सहयोग राज्य को मिलता रहा है।

जादवपुर विश्वविद्यालय में 'कश्मीर मांगे आजादी' और 'लाल सलाम' के नारे लगाने वालों को उखाड़ फेंकेंगे : शुभेंदु अधिकारी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को जादवपुर विश्वविद्यालय परिसर में 'कश्मीर मांगे आजादी' और 'लाल सलाम' जैसे नारे लगाने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि वह ऐसी ताकतों को 'उखाड़ फेंकने' का संकल्प ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि भगवा रंग का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी गोलपार्क से विश्वविद्यालय परिसर तक निकाली गई तीन किलोमीटर लंबी 'गेरुआ सम्मान यात्रा' का नेतृत्व करने के बाद परिसर के बाहर एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जादवपुर विश्वविद्यालय को श्री अरविंद की धरती बताते हुए कहा कि यह शिक्षा का उत्कृष्ट केंद्र है।

उन्होंने कहा कि मैं भगवा रंग का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने अपना संदेश स्पष्ट कर दिया है। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री जानता है कि जादवपुर से 'कश्मीर मांगे आजादी' और 'लाल सलाम' के नारों को कैसे मिटाना है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जादवपुर से उन लोगों को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है, जो 'कश्मीर मांगे आजादी' के नारे लगाते हैं और किसान आंदोलन का समर्थन कर चुके हैं। अधिकारी ने कहा कि वह दोबारा जादवपुर आएंगे और भगवा रंग का अपमान करने वालों को धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से 'सबक सिखाया जाएगा।' उन्होंने कहा कि वह गीता पाठ और हनुमान चालीसा के माध्यम से ऐसा करेंगे। यह स्वामी विवेकानंद की धरती है और यहां भगवा कायम रहेगा।' अधिकारी ने तीन दिवसीय वैदिक पाठ कार्यक्रम की भी घोषणा की और लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की। भगवा वस्त्र और हाथ में भगवा झंडा लेकर अधिकारी ने यात्रा का नेतृत्व किया। इसमें बड़ी संख्या में साधु-संत, नागा साधु और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान 'जय श्रीराम' के नारे लगाए गए। एक नागा साधु ने कहा कि उन्होंने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया और अपनी आस्था की रक्षा के लिए हथियार उठाए, फिर भी उनका अपमान क्यों किया जा रहा है। उन्होंने इस मुद्दे को उठाने के लिए अधिकारी का आभार जताया। जादवपुर विश्वविद्यालय में पिछले कुछ दिनों से वामपंथी छात्र संगठनों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बीच राजनीतिक और वैचारिक टकराव बढ़ा है। परिसर में झड़पों, दीवारों पर लिखे नारों और नारेबाजी को लेकर विवाद तेज हुआ है। भाजपा के एक नेता ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य भगवा रंग की 'गरिमा' कायम रखना था।

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी, सैफुल्लाह सिद्दिकी द्वारा आरडी प्रिंटिंग एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-24, सेक्टर-08, नोएडा (यूपी), से छपवा कर एन-81, बटला हाउस, जामिया नगर पुलिस स्टेशन, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित किया। सर्वाधिकार सुरक्षित, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा। (संपादक- सैफुल्लाह सिद्दिकी)